नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 58 | नोएडा, शनिवार, 28 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

जिंदगी बहुत सुंदर है, नजरिया अच्छा होना चाहिए



गुजरात से जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

एटीएस ने एके-47 और 20 जिंदा कारतूस किए बरामद

वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की तैयारी कर रहा था

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने वडोदरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मोहम्मद सहारुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। वह असम का रहने वाला है। एटीएस के मुताबिक, वह वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसके मोबाइल से एयरफोर्स स्टेशन की फोटो और वीडियो के साथ जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री भी मिली है। उसके पास से एके - 47 जैसी ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफल, 2 मैगजीन, 23 जिंदा कारतूस, जैश-ए-मोहम्मद का झंडा, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। जांच के मुताबिक, आरोपी असम से बस और ट्रेन के जरिए गुजरात आया था। वह सार्वजनिक जगहों पर आतंकी हमला करने की फिराक में था। वडोदरा में वह रेलवे स्टेशन के पास रुका हुआ था। एटीएस पिछले 6 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। गुजरात एटीएस ने 3 जुलाई को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा था। सभी को अलग अलग जिलों से पकड़ा गया। इनमें से दो की उम्र 18 और 19 साल है। ये सभी गुजरात में छुट्टरूका एक एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहे थे, ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया सके। सूचना मिलने के बाद, एटीएस ने 5 अलग-अलग टीमें बनाकर एक बड़ा अभियान चलाया था। एटीएस की टीमों ने गुजरात के कई जिलों में सर्चिंग की।



रिपोर्ट-वायुसेना की टीम रूस जाकर सिस्टम की जांच करेगी

एलओसी पर पांचवां एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से लगे 740 किलोमीटर लंबे नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पांचवां एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना है। इससे पहले चार को सीमा पर अलग-अलग जगह तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से इनके लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वायुसेना की एक टीम अगले महीने रूस जाकर इस सिस्टम का प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन करेगी। इसके फरवरी 2027 तक तैनाती के लिए तैयार होने की उम्मीद है। यह जानकारी मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने दी है। एस-400 ट्रायम्फ रूस का एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है।



भारत के पास एस-400 की 3 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन

एस-400 की एक स्क्वाड्रन में 256 मिसाइल होती हैं। भारत के पास इस वक्त 3 स्क्वाड्रन हैं, जिन्हें अलग-अलग तरफ की सीमाओं पर तैनात किया गया है। पहली स्क्वाड्रन :पंजाब में तैनात की गई है। भारत को पहली 2021 में रूस ने पहली स्क्वाड्रन सौंपी थी। यह पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर से आने वाले खतरों को रोकने के लिए है। दूसरी स्क्वाड्रन - सिक्किम (चीन सीमा) में तैनात है। भारत को यह खेप जुलाई 2022 में मिली थी। यहां से चिकन नेक पर भी निगरानी रखी जाती है। तीसरी स्क्वाड्रन- राजस्थान-गुजरात या पंजाब-राजस्थान सीमा पर तैनात है। भारत को यह खेप फरवरी 2023 में मिली। इस स्क्वाड्रन से पश्चिमी सीमा की सुरक्षा मजबूत होती है। चौथी स्क्वाड्रन - असम में तैनात है। यह अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करती है। जून 2026 में इसकी पहली खेप भारत पहुंची।

पाकिस्तान चीन से 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन और तुर्किये पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है, जबकि सऊदी अरब उसे आर्थिक मदद दे रहा है। पाकिस्तान चीन से 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है। इस सौदे की कीमत 5 अरब डॉलर यानी करीब 46,220 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से एक पनडुब्बी जून 2026 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हो चुकी है। तुर्किये पाकिस्तान की अगोस्टा-90बी पनडुब्बियों को अपग्रेड कर रहा है और उसे लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन दे रहा है। वहीं, चीन पाकिस्तान को मिसाइल दागने में सक्षम विंग लूंग-2 ड्रोन भी दे चुका है।

सुप्रीम' आदेश | **मदुरै दीपथून पर आज जलाओ दीपक**

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार से नाराज सुप्रीम कोर्ट

मंदिर ट्रस्ट निलंबित,सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ होगी तैनात

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून स्तंभ में कार्तिगई दीपम जलाने का विवाद अब न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच आदेश पालन का बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को एक विशेष निर्देश दिया था, लेकिन 24 नवंबर को निर्धारित स्थान पर दीप नहीं जलाया गया। इसके बाद अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेशों को अपनी सुविधा के अनुसार बदलना या उन पर बातचीत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे। अदालत 27 नवंबर को मदुरै के जिला कलेक्टर और तमिलनाडु के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 20 नवंबर के आदेश में 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने साफ किया कि इस सुनवाई में वह पुराने विवाद के सभी पहलुओं के बजाय अपने आदेश के पालन की जांच करेगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने पाया कि 20 नवंबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है। जबकि, मदुरै के जिला कलेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि आदेश का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निलंबित कर दिया है और दो जजों की एक समिति के जरिए मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है।



अधिकारी 'बॉस' को खुश करने में लगे हैं

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने पाया कि 20 नवंबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है। जबकि, मदुरै के जिला कलेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि आदेश का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि तमिलनाडु प्रशासन संवैधानिक अराजकता की स्थिति में है। बेंच ने कहा कि वे मदुरै के जिला कलेक्टर के शुरुआती बर्ताव से हैरान हैं। कलेक्टर के पास व्यापक शक्तियां होने के बावजूद, उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन न करने की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन पर मढ़ दी। अधिकारियों द्वारा अपने राजनीतिक वरिष्ठों के इशारे पर काम करने के आरोपों पर, पीठ ने कहा कि दावों की जांच करनी होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 28 नवंबर को दीपथून पर धार्मिक दीप जलाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इसके लिए उचिपिल्लैयार मंडपम में जल रही लौ का इस्तेमाल किया जाए, यदि वह अभी भी जल रही हो। ऐसा संभव नहीं होने पर दीप जलाने की दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। अदालत ने श्रद्धालुओं को दरगाह से सभी तरफ कम से कम 50 मीटर की दूरी रखते हुए दीप जलाने की अनुमति भी दी। यह कार्रवाई कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश का पालन न करने की वजह से की गई है। इस आदेश में मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित 'दीपाथून' पत्थर के खंभे पर एक बार दीपाम (धार्मिक दीपक) जलाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, 24 नवंबर को दीपक नहीं जलाया गया।

जाकिर नाइक के संगठन पर ऐक्शन ले सकेंगे राज्य

यूएपीए के तहत फंड-प्रॉपर्टी जब्त करने का मिला अधिकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दे दिया है। अब राज्य सरकारें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत संगठन के फंड, वित्तीय संपत्तियों और परिसरों पर कार्रवाई कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर को इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को आईआरएफ पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। यह फैसला यूएपीए की धारा 42 के तहत लिया गया है। इसके तहत राज्यों को यूएपीए की धारा 7 और 8 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। धारा 7 के तहत अधिकारी संगठन के लिए इस्तेमाल होने वाले या रखे गए फंड, बॉन्ड और अन्य प्रापर्टियों के लेनदेन पर रोक लगा सकते हैं। संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच भी की जा सकेगी। वहीं, धारा 8 के तहत संगठन की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले घर, इमारत और अन्य परिसरों को अधिसूचित कर उन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। ऐसे परिसरों में लोगों की आवाजाही और वहां मौजूद चल संपत्तियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जा सकती है।



संगठन पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को आईआरएफ पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। यह प्रतिबंध 14 नवंबर को खत्म होने वाला था। सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) और 3(3) के तहत संगठन को गैरकानूनी घोषित किया है। भारत ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को आईआरएफ पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय गंभीर आरोप थे।

2016 से भारत के बाहर है

महाराष्ट्र का रहने वाला जाकिर नाइक 2016 में विदेश यात्रा पर गया था। उसी साल केंद्र सरकार ने उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद से वह मलेशिया में रह रहा है। 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया था।

हम हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू रिवाजों से हों हमारे अंतिम संस्कार!

ईसाई परिवारों ने केरल हाई कोर्ट से लगाई गुहार,कर दी बड़ी मांग

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। धर्म चुनना किसी भी व्यक्ति की निजी आस्था और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। इसी अधिकार को लेकर केरल के एक ईसाई परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परिवार के आठ सदस्य ईसाई धर्म छोड़कर अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोल्लम जिले के



कोट्टारक्करा स्थित श्री महागणपति मंदिर में धार्मिक रस्म कराने की मांग की है। परिवार का कहना है कि मंदिर प्रशासन की ओर से करीब पांच महीने तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। अब इस मामले में केरल हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

हिंदू धर्म में आस्था, परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका- मामला केरल के कोल्लम जिले के पुनालूर क्षेत्र के एक ईसाई परिवार से जुड़ा है। परिवार के आठ सदस्य चर्च ऑफ साउथ इंडिया से जुड़े हैं। याचिकाकर्ता सूर्यलक्ष्मी एस के अनुसार, उनके पूर्वज हिंदू थे और कुरावा समुदाय से संबंध रखते थे। परिवार ने अपनी इच्छा से दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। परिवार ने 24 जून 2026 को कोट्टारक्करा श्री महागणपति मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी के सामने आवेदन दिया था। उनकी मांग थी कि मंदिर में मत परिवर्तनम यानी धर्म परिवर्तन की धार्मिक रस्म कराई जाए। लेकिन मंदिर प्रशासन ने फिलहाल इंतजाम नहीं किया है। ऐसे में उन्होंने अदालत से दखल देने की गुहार लगाई।

मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, 25 साल संख्या नहीं बदलेगी

प्रस्ताव पास,लोकसभा में बढ़ेंगी 50 फीसदी सीटें

30 को लोकसभा,2 दिसंबर को राज्यसभा में बिल आएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैबिनेट ने शुक्रवार को लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में करीब एक घंटे बैठक चली। इसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण के नए बिल को मंजूरी दी गई। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। 50 फीसदी बढ़ोतरी के बाद ये 815 हो जाएंगी। यानी 272 सीटें बढ़ेंगी। बढ़ाई गई सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। कुल सीटों की यह संख्या अगले 25 साल तक नहीं बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक, नए बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की लोकसभा में सीटों की हिस्सेदारी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम न हो। सरकार इसे 30 नवंबर को पेश करेगी।



मोदी कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को डिलिमिटेशन के जरिए महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित कानून में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान है, जबकि 2051 तक सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखा जाएगा। ये फैसला संसद के स्पेशल सेशन के लिए फिर से शुरू होने से कुछ दिन पहले आया है, क्योंकि सरकार अप्रैल में बिल के हारने के बाद इसे पास करने की एक और कोशिश करने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी है।

अप्रैल में पेश विधायी पैकेज में ये 3 बिल थे शामिल

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026-इसका उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 सीटें करना और महिला आरक्षण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एक परिसीमन आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 : इसका उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की चुनावी व्यवस्था में जरूरी बदलाव करना है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 तक हो सकती है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल होंगे। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत रणनीति बनेगी।

राजनीति | **यूपी चुनाव पर खरगे बोले-यहां गठबंधन सरकार को लाओ**

इमरान को नसीहत,जोश ठीक,लेकिन काम करना है

लखनऊ (एजेंसी)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। कहा कि गठबंधन की सरकार लानी है। मोदी-योगी को हराना है। अंदरूनी झगड़ों से जीत मुश्किल होती है। उन्होंने इमरान मसूद के जोश की तारीफ की, साथ ही गठबंधन धर्म निभाने की सलाह भी दी। कहा- हमारे इमरान मसूद हैं, रोज टीवी पर सुनता हूं, जरा जोश के साथ बात करते हैं। लेकिन हमें बातों से ज्यादा काम भी करना है। इसलिए जितना हम लोग मिलकर काम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारे अजय राय ने प्रधानमंत्री से टक्कर ली। वह थोड़े से चूक गए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहते। वह गुजरात जाकर बैठते। खड़गे कांग्रेस के संविधान बचाओ मार्च में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, खड़गे के जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। पार्टी कार्यालय से करीब 150 मीटर आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने पहले से ही थ्री लेयर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कई कोशिशों के बाद भी कांग्रेसी आगे नहीं बढ़ सके। उधर, पुलिस ने मार्च में शामिल प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा को गिरफ्तार किया।



कार्यालय से डेढ़ सौ मीटर तक ही आगे बढ़ सके कांग्रेसी

पार्टी कार्यालय से करीब डेढ़ सौ मीटर तक बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। लेकिन थ्री लेयर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उनको रोक दिया। करीब 40 मिनट तक कांग्रेसियों ने आगे जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद सहित कई सीनियर नेताओं को हिरासत में ले लिया और सबको इको गार्डन लेकर गई। अजय राय ने कहा- योगी सरकार तानाशाही कर रही। संविधान दिवस के दिन संविधान कुचलने का काम सरकार कर रही। ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। हम संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर की रैली को भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित बताया। कांग्रेस की रैली में आए सुभाष श्रीवास्तव ने कहा हम लोग कभी अंग्रेजों से नहीं डरे। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे मार्च को रोका था।

पीएम मोदी ने 23 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात

'महासागर' विजन से मजबूत होगी क्षेत्रीय साझेदारी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। नई दिल्ली में 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (आईओआरए) की 25वीं 'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स' (सीओएम) बैठक के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से हमारे लोगों को जोड़े रखा है। भारत का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को और मजबूत करना है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की 25वीं मंत्रिपरिषद बैठक में शामिल 23 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मिलकर बेहद खुशी हुई। हिंद महासागर ने हजारों वर्षों से हमारे लोगों को आपस में जोड़े रखा है। आईओआरए के अध्यक्ष के रूप में भारत, सभी साझेदार देशों के साथ मिलकर 'महासागर' (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी ऐंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स) के अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' उन्होंने पोस्ट किया, ''भारत का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और



समृद्धि को और मजबूत करना है, ताकि इस पूरे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके और सभी देशों को इसका लाभ मिल सके।'' आईओआरए मंत्रिपरिषद की 25वीं बैठक के सफल आयोजन के लिए मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भारत की सराहना की। उन्होंने पिछले एक साल के दौरान इस क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता करने के लिए भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार को इस परिषद बैठक के सफल आयोजन और हमारे यहां पहुंचने के बाद से मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए बधाई देता हूं। मैं पिछले एक वर्ष में आईओआरए की अध्यक्षता के दौरान भारत के शानदार नेतृत्व की भी सराहना करता हूं।

साथ ही, इस बैठक की तैयारी और संगठन के सहयोग एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगातार समर्थन देने के लिए आईओआरए सचिवालय की भी प्रशंसा करता हूं। ' श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने भी भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए बैठक के लिए किए गए स्वागत और व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने आईओआरए की 'ट्रोइका' व्यवस्था के तहत भारत और मॉरीशस के साथ मिलकर काम करने को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भारत और मॉरीशस दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। आईओआरए में अध्यक्षता किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती। यह दो वर्षों के लिए सभी सदस्य देशों की ओर से भरोसे के रूप में सौंपी जाती है और फिर आगे बढ़ा दी जाती है। श्रीलंका ने 2023 से 2025 तक यह जिम्मेदारी निभाई और हमने इसे पूरी तरह विश्वास के साथ भारत को सौंपा है।

लोक सभा अध्यक्ष ने श्री जी. वी. मावलंकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; सांसदों; पूर्व सांसदों ; लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री मावलंकर, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा (वर्तमान गुजरात) में हुआ था, ने भारत की संसदीय संस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1937 में अहमदाबाद से बॉम्बे विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने विधायी जीवन की शुरुआत की और 1946 तक उसके अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने छठी केंद्रीय विधान सभा की अध्यक्षता की और स्वतंत्रता पूर्व के महत्वपूर्ण वर्षों में उसका मार्गदर्शन किया । 1947 के बाद, श्री मावलंकर ने संविधान सभा (विधायी) के अध्यक्ष तथा तत्पश्चात अंतरिम संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1952 में प्रथम लोक सभा के गठन के साथ, उन्हें 15 मई 1952 को सर्वसम्मति से लोक सभा अध्यक्ष चुना गया और 27 फरवरी 1956 को उनके निधन तक उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन उत्कृष्ट रूप से किया। उनका अनुशासन और प्रतिबद्धता आज भी भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और परंपराओं को परिभाषित करती है।

नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री पर सुकेश चंद्रशेखर का ऐतराज, वकील ने भेजा कानूनी नोटिस

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। सुकेश चंद्रशेखर ने नेटफ्लिक्स पर आने वाली अपनी जिंदगी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आपत्ति जताई है। सुकेश के वकील अनंत मलिक ने नेटफ्लिक्स और इंडिया टुडे ग्रुप को कानूनी नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट्री की रिलीज रोकने की मांग की है। 'लव, स्कैम और धोखाः द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' नाम की यह डॉक्यूमेंट्री 18 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। सुकेश के वकील का आरोप है कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों में अभी गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में मुकदमों का फैसला आने से पहले उनकी जिंदगी और मामलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने साफ किया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी के मुताबिक, वकील अनंत मलिक ने नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया, नेटफ्लिक्स इंक., इंडिया टुडे ग्रुप, डॉक्यूमेंट्री के दोनों निर्देशकों और कार्यकारी निर्माता को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म की रिलीज और ट्रेलर को तब तक रोकने की मांग की गई है, जब तक संबंधित आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती। नोटिस का जवाब देने के लिए नेटफ्लिक्स और इंडिया टुडे को 72 घंटे का समय दिया गया है।

'रामायण' विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, सीजेआई बोले- पहले ही रिलीज हो चुकी है फिल्म'

नई दिल्ली । रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायणः पार्ट 1' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के मूल तथ्यों से छेड़छाड़ और भ्रामक प्रचार के जरिए दर्शकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने फिल्म के पहले ही रिलीज हो जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख चुके हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म में कई तथ्यों को गलत तरीके से दिखाए जाने की दलील दी। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि फिल्म बनाने वालों ने महाकाव्य को अपनी समझ के अनुसार पेश किया है। अगर याचिकाकर्ता की रामायण को लेकर अलग समझ है, तो वह भी उस पर फिल्म बना सकते हैं। अदालत ने वकील से कहा कि कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। उन्होंने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में फिल्म के निर्माताओं और इससे जुड़े कई लोगों के साथ-साथ केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स, निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन के नाम शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने 'शीशमहल' को जनता के लिए खोला, प्रवेश वर्मा बोले- कोविड के समय भी नहीं रुका था काम

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बंगले को 'शीश महल' कहकर संबोधित करती रही है। सरकार ने आवास के नवीनीकरण, साज-सज्जा और फर्निशिंग पर हुए खर्च को प्रमुखता से सामने रखते हुए इसे सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा, 'आज शीशमहल खोलने का उद्देश्य जनता को यह दिखाना है कि उनका पैसा कहां खर्च हुआ है। लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। जिस व्यक्ति ने एक बार दावा किया था कि वह न तो कार लेगा और न ही बंगला और सरकार से एक मामूली दो कमरों का मकान चाहता था, उसका शुरुआती प्रोजेक्ट बजट 8 करोड़ रुपये था, जो अंत में 58 करोड़ रुपये को पार कर गया।' प्रवेश वर्मा ने कहा, 'शीशमहल पार्ट 2 भी बनने जा रहा था, जिसे हमारी सरकार ने आते ही रोक दिया। दिल्ली की जनता मुझे बार-बार कहती थी कि हमको भी शीशमहल दिखाइए। मीडिया के बहुत सारे लोगों ने भी हमें कहा कि हमको शीशमहल लेकर चलिए। तो ऐसे में अंदर के सारे सामान और वस्तुओं के पैसे कहां खर्च हुए, उन सभी के प्राइस टैग लगाए गए हैं। तो हर प्राइस टैग के साथ उसका बिल नंबर भी लिखा हुआ है।

दिल्ली जल बोर्ड मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द करने की मांग

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली एसीबी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीबी की याचिका पर सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। एसीबी ने ट्रायल कोर्ट के 3 सितंबर के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस मामले में सत्येंद्र जैन की अचानक और जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी को लेकर एसीबी की आलोचना की थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, वह प्रक्रिया के अनुरूप नहीं लगती। अदालत ने इसी आधार



पर जैन को जमानत दी थी।

अब एसीबी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है और जमानत रद्द की जानी चाहिए। एसीबी ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आरोपी के बाहर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणियों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी।

दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं का यह मामला काफी पुराना है। आरोप है कि जल बोर्ड के कामकाज में नियमों की अनदेखी की गई और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। एसीबी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाया है। जैन पर पद का दुरुपयोग और अनियमितताओं में भूमिका का आरोप है। हालांकि, जैन ने शुरू से ही सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है।

'आप' नेता सत्येंद्र जैन पहले भी कई मामलों में जांच का सामना कर चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि बार-बार नए मामलों में नाम जोड़कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं, जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है।

तरुण चुघ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले-

तीन पीढ़ियों ने अंबेडकर की सोच को कुचलने का काम किया

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर की मूल सोच गरीबों तक तरक्की पहुंचाने की थी, लेकिन कांग्रेस की तीन पीढ़ियों ने लगातार उसे दबाने का काम किया। काका कालेलकर आयोग से लेकर मंडल आयोग और आपातकाल तक का जिक्र करते हुए चुघ ने राहुल गांधी से कई सवाल पूछे और पीएम मोदी के नेतृत्व में संविधान की मूल आत्मा को सशक्त करने का दावा किया। सांसद तरुण चुघ ने कहा, डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माण करने वाली समिति को हम नमन करते हैं और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव



अंबेडकर की मूल सोच थी कि देश के हर गरीब तक तरक्की पहुंचे और हर नागरिक देश के निर्माण में भागीदार बने, लेकिन कांग्रेस की तीन पीढ़ियों ने उस सोच को दबाने और कुचलने का काम किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश जानना चाहता है कि 1950 के दशक में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट बनी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे क्यों रोका? क्योंकि उसमें वंचितों को अधिकार देने की बात थी। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट की बात आई, तो आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उसे क्यों दबाया? देश यह भी जानना चाहता है कि भारत के संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ 1975 में आपातकाल लगाकर किया गया था। देश की न्याय व्यवस्था को खुली चुनौती किसी ने दी थी, तो वह आपकी दादी इंदिरा गांधी ने दी थी।

सांसद ने कहा कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो डॉ. भीमराव अंबेडकर के 49 फीसदी आरक्षण संबंधी सपने को लागू करने का काम किया, लेकिन आपके पिता राजीव गांधी ने संसद में उसका सबसे लंबा विरोध भाषण दिया था।

'भगवान मुरुगन के भक्तों की ऐतिहासिक जीत'

दीपम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नितिन नवीन ने किया स्वागत

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया। उन्होंने मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून में पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने के मामले में कोर्ट के फैसले को भगवान मुरुगन के भक्तों की 'ऐतिहासिक जीत' बताया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्य सचिव एम. साई कुमार, पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई)



विभाग के अधिकारियों और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पारंपरिक दीप जलाने के आदेश का कथित जानबूझकर पालन नहीं करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नितिन नवीन ने कहा, 'भगवान मुरुगन के प्रत्येक भक्त के लिए यह ऐतिहासिक जीत है!' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इंडिया गठबंधन की 'सनातन विरोधी मानसिकता' को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कल थिरुपरनकुंद्रम दीपाथून में पारंपरिक दीप जलाने का आदेश देकर और तमिलनाडु के अधिकारियों को उनके राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर काम करने के लिए फटकार लगाकर इंडी गठबंधन सरकार की सनातन विरोधी मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर दिया है।' नितिन नवीन ने कहा कि भारत की पवित्र परंपराओं को कोई राजनीतिक साजिश रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा, 'भगवान मुरुगन की दिव्य कृपा सभी भक्तों की रक्षा करे और उन्हें साहस तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे।' इससे पहले न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अधिकारियों से पूछा था कि 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने उस आदेश में विवादित स्थल पर पारंपरिक दीप जलाने का निर्देश दिया था। घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया घटनाओं की श्रृंखला से संकेत मिलता है कि कार्यकारी अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर काम किया।

दिल्ली के बवाना में 12.2 किलो गांजा के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने शुक्रवार को बवाना इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12.205 किलो संदिग्ध गांजा बरामद किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय मरजीना और 19 वर्षीय कृष्मा के रूप में हुई है।

दोनों आरोपी बवाना के जेजे कॉलोनी की निवासी हैं। उनके पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, ये गिरफ्तारियां 24 नवंबर को उस समय हुईं जब पुलिस दल नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में शाम की नियमित गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान दल ने बावना के जेजे कॉलोनी के बी-ब्लॉक में राजस्थानी मंदिर वाली गली के पास दो महिलाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में बैग ले जाते हुए देखा। पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया और उनके बैग की तलाशी ली, जिसमें संदिग्ध गांजा बरामद हुआ।

बरामदगी के बाद, नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 674/2026, दिनांक 25 नवंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20(बी)(दो)(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, चोरी के 181 वाहनों के साथ 36 ऑटोलिफ्टर गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहदरा जिले में वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। 'ऑपरेशन चक्र' नाम से चलाए गए इस अभियान के तहत पुलिस ने महज सात दिनों में चोरी के 181 वाहन बरामद किए और 36 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने आईएएनएस से बातचीत में इस अभियान की पूरी जानकारी दी। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि शाहदरा जिले में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए 18 नवंबर से 25 नवंबर तक 'ऑपरेशन चक्र' चलाया गया। इस अभियान के लिए कुल 15 टीमें गठित की गई थीं। इन टीमों में जिले के हर थाने के पुलिसकर्मियों के साथ-साथ स्पेशल स्टाफ, एटीएस और एएसपीएल जैसी विशेष इकाइयों के जवानों को भी शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी टीमों ने बेहद मेहनत और समन्वय के साथ काम किया। लगातार की गई छापेमारी, निगरानी और सूचना तंत्र के दम पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पूरे अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 181 वाहन बरामद किए। इनमें अधिकांश दोपहिया वाहन बताए जा रहे हैं।

दिल्ली से बिहार के 13 शहरों तक सीधी बस सेवा

दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट से दिल्ली और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं का शुभारंभ किया। दोनों राज्यों के बीच बस सेवाओं के लिए एमओयू साइन किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत मौजूद रहे। इससे पटना, गयाजी, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर सहित बिहार के 13 शहरों एवं क्षेत्रों तक दिल्ली से सीधी बस सेवाओं का विस्तार होगा। इस संबंध में सीएम रेखा



गुप्ता में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए तस्वीरें भी साझा कीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बिहार के लोगों ने अपने परिश्रम से दिल्ली को संवारा है और अपनी संस्कृति से दिल्ली को समृद्ध किया है। उनकी खुशियों में बिहार भी है और दिल्ली भी। आज दोनों राज्यों के बीच का सफर और आसान बनाने की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कश्मीरी गेट से दिल्ली और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही, 18 बस रूटों के संचालन के लिए दोनों राज्य सरकारों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पटना, गयाजी, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर सहित बिहार के 13 शहरों एवं क्षेत्रों तक दिल्ली से सीधी बस सेवाओं का विस्तार होगा। जब भी अपनों से मिलने का मन हो, आसानी से घर जा सकें, यही हमारा प्रयास है। इस पहल के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखा कि इस पहल के लिए बिहार सरकार का हृदय से आभार। कार्यक्रम में कैबिनेट सहयोगी डॉ. पंकज कुमार सिंह जी, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इसी बीच एक अन्य कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने को लेकर 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और 9 सपोर्ट वाहनों को दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित किया।

कार्तिगई दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विहिप ने किया स्वागत

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने तमिलनाडु के कार्तिगई दीपम विवाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि न्यायालय का हस्तक्षेप हिंदू आस्था और कानून के शासन की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे तमिलनाडु सरकार और हिंदू विरोधी राजनीति पर करारा तमाचा बताया। आलोक कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था, लेकिन 24 नवंबर को दीप नहीं जलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों और प्रशासनिक तंत्र ने मिलकर न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 28 नवंबर को दीपथून पर दीप प्रज्वलित करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। न्यायालय ने मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित कर मद्रास उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन को रिसीवर नियुक्त किया है। सीआरपीएफ को मंदिर और दरगाह दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को दरगाह से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर दीप जलाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मदुरै के जिलाधिकारी और मंदिर न्यासी मंडल के सदस्यों को अवमानना के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया 20 नवंबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना और मदुरै में प्रशासनिक अराजकता पर चिंता जताई है।

संक्षिप्त डायरी

बाइक सवार को घसीटने वाले आरोपी को दस साल कारावास की सजा

अनप्लग इंडिया

नोएडा। जिला न्यायालय ने गंगा स्नान कर बाइक से घर लौट रहे व्यक्ति की मौत के मामले में संभल के अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी चालक ने कार में फंसे बाइक सवार को 17 किलोमीटर तक घसीटा था। अदालत ने दोषी पर 71 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ना राशि जमा नहीं करने पर साढ़े आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना की जांच में सामने आई सीसीटीवी फुटेज अभियोजन के अनुसार, सुखपाल सिंह 3 नवंबर 2017 की रात गढ़गंगा से गंगा स्नान कर बाइक से अकेले घर लौट रहे थे। अगली सुबह तक वह घर नहीं पहुंचे तो भाई नरेंद्र और परिजन तलाश में निकले। बादलपुर थाने की धूममानिकपुर चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे उनकी टूटी बाइक मिली पर सुखपाल का पता नहीं चला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 11 बजे किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। अस्पतालों में खोजबीन के बाद परिजन सिकंदराबाद थाने पहुंचे थे। जहां पता चला कि बुलंदशहर जिला अस्पताल की मोर्चरी में अज्ञात शव रखा है। परिजनों ने शव की पहचान सुखपाल के रूप में की थी। शव सबसे पहले जोखाबाद के तत्कालीन ग्राम प्रधान धीरेंद्र ने सिकंदराबाद क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी थी। डॉक्टर के अनुसार मृतक के शरीर पर चार जगह मृत्यु-पूर्व चोटे के निशान मिले थे। 6 नवंबर 2017 को बादलपुर कोतवाली पुलिस ने सड़क दुर्घटना मानकर जांच शुरू की थी। करीब डेढ़ माह बाद 18 दिसंबर 2017 को नरेंद्र ने एसएसपी को प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि लुहारली टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में टाटा सूमो के नीचे एक शरीर फंसा दिखता है। आरोप था कि चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बत्तियां बुझाईं और बाद में शव सुनसान जगह फेंक दिया था। उन्होंने धारा 304 बढ़ाने की मांग की थी। अगले दिन उन्होंने फुटेज वाली पेनड्राइव भी पुलिस को सौंपी। जांच के बाद पुलिस ने अतीक के खिलाफ धारा 279, 427, 201 और 304 में आरोप-पत्र दाखिल किया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें मुकदमे में अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश हुए। बचाव पक्ष ने कहा कि यह मामूली सड़क दुर्घटना थी। जिसे अनावश्यक रूप से गैर- इरादतन मानव वध का रूप दिया गया। कोई चश्मदीद नहीं है। वाहन की तकनीकी जांच रिपोर्ट में लोहे की रॉड या एंगल का जिक्र नहीं है और पहली तहरीर की तुलना में बाद के बयानों में नई बातें जुड़ती गईं। इसलिए अभियोजन की कहानी समय के साथ बदली है। वहीं डीजीसी ब्रहजीत भाटी ने बताया कि आरोपी ने फंसे हुए व्यक्ति को जानते हुए गाड़ी करीब 17 किलोमीटर चलाई, जो सामान्य लापरवाही नहीं, बल्कि जान जाने की संभावना जानते हुए किया गया कृत्य है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को मिली सजा अदालत नहीं माना कि सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह प्रमाणित है। उसे अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता और ऐसे में परिस्थितिया स्वयं बोलती हैं। वाहन में शव फंसा होना, बत्तियां बंद रखना, ट्रक के पीछे छिपने की कोशिश और कुछ दूर आगे शव मिलना, ऐसी कड़ी हैं जो बताती हैं कि अपराध आरोपी ने ही किया है।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर इंजीनियर से 14 लाख रुपये ठगे

अनप्लग इंडिया

नोएडा। साइबर अपराधियों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 14 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने टेलीग्राम के माध्यम से पीड़ित से संपर्क किया था। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने कई बार में ट्रांसफर किए रुपये ग्रेटर नोएडा के टेकजोन-चार स्थित स्प्रिंग मीडोस निवासी रत्नेश कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह शेयर बाजार में निवेश करने में रुचि रखते हैं। पांच अक्तूबर को उनके पास टेलीग्राम के माध्यम से एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया और उनके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश पर निवेश करके कई गुना अधिक रकम प्राप्त करने का भरोसा हुआ। मैसेज के जरिये बातचीत होने के बाद आरोपियों ने उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर जोड़ लिया। ग्रुप पर 200 से अधिक लोग जुड़े हुए थे। ग्रुप पर जुड़े लोग शेयर बाजार में निवेश की जानकारी साझा कर रहे थे। रकम ट्रांफर करने के बाद स्क्रीन शॉट डाल रहे थे। यही नहीं वह निवेश करने के बाद मुनाफे की जानकारी भी दे रहे थे। आरोपियों पर विश्वास करके उन्होंने भी निवेश करने की इच्छा जताई। इस पर आरोपियों ने एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड कराया। उन्होंने जालसाजों के कहे अनुसार रकम भेजना शुरू कर दिया। निवेश करने के कुछ समय बाद रकम कई गुना अधिक दिखाई देने लगी। उन्होंने भरोसा करके 25 अक्तूबर तक कई बार में 14 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने रुपये निकालने के लिए कहा तो आरोपियों ने मना कर दिया। वह विभिन्न तरह के शुल्क के रूप में और रकम की मांग करने लगे। जब उन्होंने रकम देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया। तब जाकर उन्हें ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने फौरन एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेनो में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 11 स्थानों पर विशेष निगरानी

अनप्लग इंडिया

नोएडा। ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण ने अभियान तेज कर दिया है। क्षेत्र में चिह्नित 11 हॉटस्पॉट यानी प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके लिए चार वरिष्ठ प्रबंधकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसीईओ, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी भी रोजाना स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी और उपाय अधिकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ग्रेटर नोएडा के सीईओ डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर चार वरिष्ठ प्रबंधकों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें अपने- अपने क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्यों की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरक्त वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर 32 नई एंटी स्मॉग गन का संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषणकारी कणों को नियंत्रित किया जा रहा है। पेड़ों की पत्तियों पर जमी धूल को भी धोया जा रहा है। धूल को रोकने के लिए 107 वाटर टैंकर लगाए हैं। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुख्य सड़कों की सफाई के लिए 14 मशीनें लगातार चल रही हैं। अधिकारी के मुताबिक निदेर्शों का पालन नहीं करने पर प्राधिकरण ने अब 36 निर्माणकताओं को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही नियमों और निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन पर कुल 48.10 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में धूल पर रोकथाम लगाकर लोगों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण रहित बनाने के लिए सहयोग करें। कचरे को इधर-उधर न फेंककर सिर्फ डस्टबिन में डालें। कचरे को न जलाएं और कहीं भी धूल उड़ती दिखे तो इसकी सूचना प्राधिकरण को अवश्य दें।

फजीवड़ि के मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

अनप्लग इंडिया

नोएडा। अदालत ने फर्जी फर्मों के बिलों के जरिए करीब 2.29 करोड़ रुपये का भुगतान कराने के आरोपी विशाल भदौरिया को सशर्त जमानत दी है। यह मुकदमा कंपनी के महाप्रबंधक (एचआर कंप्लायंस एवं एडमिन) मुकेश तोमर की तहरीर पर 15 सितंबर 2026 को थाना फेस-2 में दर्ज हुआ था।एफआईआर के मुताबिक विशाल भदौरिया, प्रसाद कुमार परिडा, विनीत कुमार शर्मा और आशिस कुमार नायक ने मिलकर नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच केडीएन निट्स एंड फैब, अपूर्वा ट्रेडर्स और एएस ट्रेडर्स नाम की तीन फर्जी फर्में बनाईं। इन फर्मों के नाम पर ऐसे सामान के बिल तैयार किए गए, जिसकी कंपनी को कभी आपूर्ति ही नहीं हुई।

सुप्रीम आदेश से छह साल के संघर्ष के बाद मिली रजिस्ट्री, पांच खरीदारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

अनप्लग इंडिया

नोएडा। शहर के पॉश इलाकों में शुमार सेक्टर-94 स्थित बहुचर्चित 'सुपरटेक सुपरनोवा' प्रोजेक्ट के सैकड़ों घर खरीदारों के लिए गुरुवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। वर्षों के लंबे इंतजार, कानूनी दांवपेच और अनिश्चितता के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट के 'नोवा ईस्ट' और 'नोवा वेस्ट' टावरों में फ्लैटों की रजिस्ट्री (सब-लीज डीड) की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। पहले दिन कुल पांच फ्लैट खरीदारों ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर अपने सपनों के आशियाने का कानूनी मालिकाना हक हासिल किया। इस ऐतिहासिक शुरूआत के साथ ही इन दोनों टावरों के शेष 492 फ्लैट खरीदारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है और उन्हें भी जल्द ही अपने घरों की रजिस्ट्री होने की पुख्ता उम्मीद जग गई है। 2019 से दिवालिया प्रक्रिया के फेर में अटकी थी रजिस्ट्री सुपरनोवा प्रोजेक्ट के खरीदारों के लिए यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। वर्ष 2019 से ही बिल्डर कंपनी के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया (इंसॉल्वेंसी) और अन्य कानूनी अड़चनों के कारण यहां फ्लैटों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। हालात यह थे कि बड़ी संख्या में खरीदार अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी लगाकर फ्लैटों में रहने तो आ गए थे, लेकिन कागजों पर वे अपने ही घर के मालिक नहीं बन पाए थे। करीब छह साल तक चले इस लंबे इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद रजिस्ट्री का दरवाजा खुलना खरीदारों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मिली सफलता रजिस्ट्री शुरू होने के पीछे खरीदारों का लंबा संघर्ष और न्यायालय का हस्तक्षेप प्रमुख रहा है। पहले दिन रजिस्ट्री कराने वाले पांच भाग्यशाली खरीदारों में शामिल नरेश कुमार नंदवानी ने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्ष 2019 में फ्लैट खरीदकर यहां रहने पहुंचे नरेश कुमार ने बताया कि बीते साल दिसंबर महीने में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करते हुए आदेश पारित कर दिया गया था। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासनिक औपचारिकताओं, बकाया के समायोजन और खरीदारों के दस्तावेजों के गहन सत्यापन (वेरिफिकेशन) में कई महीने का समय लग गया। इन सभी प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद गुरुवार को आखिरकार रजिस्ट्री की प्रक्रिया धरातल पर उतर सकी। छह साल के संघर्ष के बाद बुजुर्ग खरीदार की आंखें हुईं नम रजिस्ट्री कराने के बाद नरेश कुमार नंदवानी बेहद भावुक और उत्साहित नजर आए। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद जीवन के सुकून भरे पल बिताने के उद्देश्य से यहां फ्लैट खरीदा था। लेकिन 2019 में पजेशन लेने के बाद से ही वे मालिकाना हक यानी रजिस्ट्री के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे और कानूनी प्रक्रियाओं से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, ₹करीब छह साल के निरंतर संघर्ष और मानसिक तनाव के बाद गुरुवार को जब मेरे नाम पर फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, तो वह मेरे जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक बन गया। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह घर कानूनी रूप से मेरा है।₹ नरेश कुमार के साथ ही चार अन्य खरीदारों ने भी गुरुवार को सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई। शेष 492 खरीदारों के लिए जगी नई उम्मीद नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावर में कुल 497 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ है। पहले दिन पांच खरीदारों की रजिस्ट्री संपन्न होने से अन्य 492 खरीदारों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक रजिस्ट्री न होने के कारण इन खरीदारों को कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मालिकाना हक के दस्तावेज न होने से वे न तो अपने फ्लैट को जरूरत पड़ने पर बेच पा रहे थे, न ही उस पर किसी प्रकार का बैंक लोन या अन्य वित्तीय सुविधा ले पा रहे थे। इसके अलावा, नोएडा प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम दर्ज न होने से हमेशा एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता था।



नार्वे के प्रतिनिधि मंडल ने छात्राओं से किया संवाद



अनप्लग इंडिया

नोएडा। सेक्टर-44 स्थित महामाया बालिका इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल ने छात्राओं से मुलाकात की। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं ने करियर और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवाल पूछे। विद्यालय में सोप्रा की ओर से स्मार्ट स्क्रीन और कंप्यूटर सेंटर भी स्थापित किया गया है। इससे छात्राओं को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। ----प्राधिकरण के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापनग्रेटर नोएडा । सेक्टर-3 के बी-ब्लॉक की समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने प्राधिकरण को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने, सफाई व्यवस्था सुधारने, पार्कों के रखरखाव और बाउंड्री वॉल बनाने की मांग उठाई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सत्यवीर नेता जी ने बताया कि पिछली बैठकों में उठाए गए कुछ मुद्दों पर काम शुरू हो चुका है। आरडब्ल्यूए महासचिव सत्यवीर नागर ने कहा कि ब्लॉक में मूलभूत सुविधाएं बेहतर करवाना ही प्राथमिकता है। इस दौरान अर्जुन अवाना, विवेक चौहान, इन्द्र भाटी, पवन शर्मा, समीर पांडे, राजीव शहरावत, विनोद कुमार और अभिषेक सिंह मौजूद रहे।

जिले में सड़क दुर्घटना में घायल 310 घायलों को मिला मुफ्त उपचार, बचा जीवन

अनप्लग इंडिया

नोएडा। जिले में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए पीएम राहत योजना के तहत अभी तक सड़क हादसों के 310 घायलों को मुफ्त उपचार दिया गया है। इनमें 305 घायलों का उपचार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के चिंहिंत अस्पतालों में किया गया। वहीं, पांच घायलों का दुर्घटना के बाद अन्य जिलों के चिंहिंत अस्पतालों में इलाज कराया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ.उदित नारायण पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित और निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में गौतमबुद्ध नगर निरंतर प्रभावी कार्य कर रहा है। योजना के तहत 310 घायलों को उपचार उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कुल 43 अस्पतालों का चयन किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों के आंकड़ों के अनुसार, कुल 310 लाभार्थियों का चयनित अस्पतालों में इलाज कराया गया है। इनमें जिम्स अस्पताल में 204 मरीज, शारदा अस्पताल में 75 मरीज, शारदा अस्पताल शारदा केयर हेल्थसिटी में 22 मरीज, न्यू जेवर अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में दो मरीज, श्री राम सिंह मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में एक मरीज और एसजेएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया गया है। अन्य जनपदों में संतोष मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गाजियाबाद में दो मरीज, नवीन अस्पताल, गाजियाबाद में एक मरीज, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट, बरेली में एक रोगी, टीएमएचआरसी मुरादाबाद में एक मरीज का इलाज किया गया है। सात दिनों तक कैशलेस उपचार की सुविधा उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हादसे की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी भय या संकोच के घायलों की मदद करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल कर घायलों को नजदीकी चिंहिंत अस्पताल पहुंचाएं, ताकि गोल्डन आवर में समय पर उपचार देकर उनका जीवन बचाया जा सके।



विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन

अनप्लग इंडिया

नोएडा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संविधान दिवस के अवसर पर ह्यविकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम-संविधान दिवस विशेषह्न का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेक्टर 62 स्थित दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य थीम ह्यनशा मुक्त युवाझविकसित भारतह्न रही। इसमें संस्थान के विद्यार्थियों एवं माय भारत के युवा स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सांसद डॉ. महेश शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, एकता और अखंडता का आधार है। युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति जागरूकता और उसके आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथि इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथियों में पैरालंपियन सुवर्णा राज, न्यायमूर्ति भंवर सिंह, महानिदेशक डीएमई डॉ. कोमल विग, निदेशक डीएमई डॉ. राजिंदर रंधावा, विभागाध्यक्ष लॉ स्कूल डॉ. नेहा शर्मा, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से कार्यक्रम अधिकारी डा. श्वेता खुराना, शिवेंद्र सिंह, प्रियांशु चौधरी आदि उपस्थित रहे। नशा मुक्त समाज के लिए युवाओं की भूमिका कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना तथा मादक पदार्थों एवं तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर युवाओं को विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका तथा नशे की समस्या से व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता वीडियो का प्रदर्शन, अतिथियों द्वारा अनुभव एवं विचार साझा करना तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इसके माध्यम से प्रतिभागियों ने संवैधानिक मूल्यों, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डीएमई के विद्यार्थियों एवं माय भारत के युवा स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता रही।



बच्चे के हाथ टूटने के मामले में दनकौर कोतवाली का किया घेराव

अनप्लग इंडिया

नोएडा। दनकौर यमुना सिटी के सेक्टर 25 स्थित सरदार पटेल विद्यालय के स्कूल में छात्र के दोनों हाथ टूटने के मामले में पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकताओं के साथ गुरुवार को दनकौर कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण और यूनियन के कार्यकताओं ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मामले में एसीपी तृतीय रवि शंकर द्वारा पीड़ित की तहरीर रोजनामचे में दर्ज करने और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन पर ही प्रदर्शनकारी शांत हुए।

परिजनों ने स्कूल पर लगाए आरोप सरदार पटेल स्कूल में 23 नवंबर को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कक्षा 6 के छात्र हर्षित को रस्सी से गिरने के कारण चोट लग गई थी। इस घटना में छात्र हर्षित के दोनों हाथ टूट गए थे। नाक मुंह और चेहरे पर भी चोट पहुंची थी। परिजनों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे का उपचार नहीं कराया। इसके बाद 24 नवंबर को पीड़ित के अधिवक्ता चाचा सूरज ने दनकौर कोतवाली में तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद 25 नवंबर को पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने स्कूल पर धरना देकर प्रदर्शन किया था। लेकिन स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल ने पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों से वार्ता नहीं की। इस बात से नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकताओं ने कोतवाली का घिराव करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तहरीर दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन गुरुवार को 10:00 बजे सैकड़ों किसान यूनियन के कार्यकर्ता और ग्रामीण पीड़ित पक्ष के लोग दनकौर कोतवाली पर धरना देकर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान दनकौर कोतवाल भी प्रदर्शनकारियों के बीच नहीं आ सके। इस कारण लोगों का गुस्सा बढ़ गया। मौके पर एसीपी तृतीय रवि शंकर पहुंचे उन्होंने ग्रामीणों और किसान यूनियन के कार्यकताओं से बातचीत की। काफी देर तक हुई वार्ता कहासुनी के बाद के पीड़ित पक्ष की तहरीर रोजनामचे में दर्ज की गई।



बोर्ड बैठक: 11327 आवंटियों को आवास बनाने के लिए एक वर्ष अतिरिक्त मिला

अनप्लग इंडिया

नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक में आवंटियों, किसानों और निवेशकों को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। अब 11327 आवासीय भूखंड खरीदारों को आवास बनाने के लिए मिलने वाली निशुल्क समय सीमा एक साल और बढ़ा दी गई है। भूमि की उपलब्धता ना होने और आवंटियों को बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते प्राधिकरण ने इस बार यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे भूखंड खरीदारों को काफी राहत मिली है। इसके अलावा प्राधिकरण ने 12 अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है।गुरुवार को यमुना विकास प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है। बताया गया कि यमुना प्राधिकरण वर्ष 2009 से अब तक करीब विभिन्न आवासीय भूखंड योजना के तहत अलग अलग सेक्टर में 30981 भूखंडों का आवंटन कर चुका। वर्ष 2009 में पहली आवासीय भूखंड योजना के तहत 20406 भूखंड आवंटित किए थे। शेष करीब 10575 अन्य योजना के तहत आवंटित किए गए है। इनमें 18,411 की चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें 14272 की रजिस्ट्री हो चुकी है। वर्तमान में 12570 भूखंडों की चेकलिस्ट व 4139 भूखंडों की रजिस्ट्री बची है। अफसरों के मुताबिक आवास न बनने का मुख्य कारण, भूमि की उपलब्धता ना होने से खरीदारों को कब्जा न मिल पाना और भूखंड विकसित नहीं होना है। करीब 17 वर्षों बाद भी यमुना सिटी के सेक्टरों में बिजली, पानी, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सेक्टरों में आवंटियों के भूखंडों पर आज भी खेती हो रही है। ऐसे में प्राधिकरण ने इन आवंटियों को मकान बनाने के लिए 31 दिसंबर 2027 तक का समय दिया है। वर्तमान में शहर में 2945 आवंटी अपना आवास बनाकर प्राधिकरण से कंप्लीशन प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा बोर्ड के समक्ष 46 नए सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान भी प्रस्तुत किया गया, भविष्य में इसी मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र में जलापूर्ति, सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था होगी।एयरपोर्ट के लिए भूमि खरीद पर 565.15 करोड़ खर्चवित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 अक्तूबर 2026 तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां 7,071.48 करोड़ रुपये दर्ज की गईं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में प्राप्त 1,746.38 करोड़ रुपये से चार गुना अधिक हैं। इस वर्ष भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 8,000 करोड़ रुपये के बजट में से 4,985.47 करोड़ रुपये भूमि खरीद एवं अधिग्रहण पर खर्च किए गए जोकि कुल बजट का 62.32 प्रतिशत है। जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण पर 565.15 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, निर्माण एवं विकास कार्यों पर 383 करोड़ और विशेष परियोजनाओं के लिए एनएचएआई को 555.38 करोड़ रुपये जारी किए गए।---निजी बिजनेस पार्क और रेस्को नीति को अपनायायीडा ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025 को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। बोर्ड की मंजूरी के बाद अब प्राधिकरण इस नीति के तहत सेक्टरों को चिन्हित करने, भूखंडों का नियोजन कराने और योजना का ब्रोशर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा खर्च में बचत के लिए भी कदम उठाया है। प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित संस्थानों की छतों पर रेस्को पद्धति से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन्वेस्ट यूपी से प्राप्त लैंड फैसिलिटेशन लेटर और निवेश सारथी पोर्टल पर मिल रहे निवेश प्रस्तावों को देखते हुए प्राधिकरण ने किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कॉर्पस फंड की धनराशि खर्च करने के लिए नियमावली तैयार की है। इसके तहत कॉर्पस फंड में शामिल विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया है।



संपादकीय

मुट्ठी में दुनिया और छूटता हाथ!

एक दिन ऐसा भी आएगा जब मोबाइल की बैटरी खत्म होगी, इंटरनेट बंद होगा, सोशल मीडिया पर हलचल थम जाएगी। उस समय हमारे पास कौन होगा? हजारों ऑनलाइन मित्र या वही अपने, जिन्हें हमने कभी समय दिया था? मशीनें हमारी आवाज सुन सकती हैं, लेकिन हर बार हमारा दर्द नहीं समझ सकतीं। स्क्रीन हमें मनोरंजन दे सकते हैं, लेकिन हर बार अपनापन नहीं दे सकते। दुनिया को मुट्ठी में रखना बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अपनों का हाथ थामे रखना उससे भी बड़ी कामयाबी है।



आज इंसान के हाथ में पूरी दुनिया है। एक छोटे से मोबाइल में हजारों किताबें हैं, लाखों जानकारियां हैं, मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं और सात समंदर पार बैठे व्यक्ति से बात करने की सुविधा है, लेकिन एक अजीब विडंबना देखिए, दुनिया से जुड़ता जा रहा इंसान अपने ही घर में बैठे लोगों से दूर होता जा रहा है। कभी घरों में शाम होते ही रौनक हुआ करती थी। कोई दिनभर की कहानी सुनाता था, कोई अपनी परेशानी बताता था, तो कोई बिना किसी खास वजह के हंसी-मजाक कर लिया करता था। घर के आंगन में बैठकर चाय पीना भी एक उत्सव हुआ करता था। आज वही आंगन सूना है। बैठक में लोग मौजूद हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग-अलग मोबाइल स्क्रीन में कैद है। क्या सचमुच हमने तरक्की कर ली है या तरक्की की दौड़ में जीने का सलीका ही भूल गए हैं? आज मां अपने बेटे को आवाज लगाती है, बेटा मोबाइल में व्यस्त है। पिता अपनी बात कहना चाहते हैं, बेटी ऑनलाइन दुनिया में मशगूल है। पति-पत्नी एक ही कमरे में बैठे हैं, मगर बातचीत किसी तीसरे माध्यम से हो रही है। घर में चार लोग हैं, चार मोबाइल हैं और चारों की दुनिया अलग-अलग है। कभी बच्चे दादा-दादी से कहानियां सुनकर बड़े होते थे। आज कहानियां मोबाइल सुनाता है और दादा-दादी बच्चों का इंतजार करते रह जाते हैं। तकनीक ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन सवाल तकनीक के विरोध का नहीं, बल्कि उसके गुलाम बन जाने का है। मोबाइल हमारा सेवक था, हमने उसे अपना मालिक बना लिया। आज सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन मुसीबत के समय कंधा देने वाला एक मित्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जन्मदिन पर सैकड़ों शुभकामनाएं आती हैं, मगर बीमारी में हाल पूछने वाले गिने-चुने लोग ही होते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत समय है और आज इंसान के पास समय ही नहीं है। मां-बाप बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े और बेहतर भविष्य देने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को सिर्फ सुविधाएं चाहिए? उन्हें माता-पिता का समय भी चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात बिना टोके सुने, उनकी असफलता पर डांटने के बजाय उनका हौसला बढ़ाए। इसी तरह बुजुर्गों को महंगे उपहारों से ज्यादा दो पल का अपनापन चाहिए। याद रखिए, बुजुर्गों को अकेलापन उम्र नहीं, अपनों की व्यस्तता देती है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम ऑनलाइन दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन घर में किसी अपने की पुकार सुनने में देर कर देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए हमारे पास समय है, मगर पिता की पुरानी कहानी सुनने के लिए समय नहीं। किसी की तस्वीर पर 'दिल वाला निशान' लगाने में हमें एक सेकंड लगता है,

अब भारत में ही पूरा होगा विश्वस्तरीय शिक्षा का सपना



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक नई दिल्ली

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपना देश छोड़कर विदेश जाना पड़ता था। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अनेक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को देश में रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिल सकते हैं। यह परिवर्तन केवल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाओं से भी जुड़ा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2026 को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें देश में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति और भारतीय शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर चर्चा की गई। मंत्रालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार, भारत में लगभग 21 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए 17 आशय पत्र जारी किए हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली के संस्थान शामिल हैं।

इन आँकड़ों को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्यरत संस्थानों और आशय पत्र प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या अलग-अलग श्रेणियों को दर्शाती है। आशय पत्र किसी प्रस्तावित परिसर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति का संकेत है। इसे परिसर का संचालन आरंभ होने अथवा विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2023 में इसके लिए नियामकीय व्यवस्था निर्धारित की। इसके अंतर्गत विदेशी संस्थानों के प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है। आयोग की स्थायी समिति आवेदन पर विचार करती है और उसकी अनुशंसा के आधार पर आशय पत्र जारी किया जाता है। परिसर की तैयारी पूरी होने के बाद शैक्षणिक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी संस्थानों को भारत में अवसर उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता और नियामकीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने मूल परिसर के अनुरूप शैक्षणिक स्तर बनाए रखना होगा। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली योग्यताओं को संबंधित भारतीय उच्च शिक्षण योग्यताओं के समकक्ष मान्यता देने का प्रावधान भी है। इससे विद्यार्थियों को उपाधियों की मान्यता संबंधी अनिश्चितताओं से राहत मिल सकती है।

विदेशी विश्वविद्यालयों की भारतीय परिसरों में उपस्थिति अब केवल प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के क्वीन्स विश्वविद्यालय बेलफास्ट ने शैक्षणिक गतिविधियाँ आरंभ की हैं। ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भी भारत में अपना परिसर स्थापित किया है। जून 2026 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले साउथैम्पटन और लिवरपूल विश्वविद्यालयों को भी ऐसे पत्र मिल चुके थे।

इन संस्थानों के विस्तार से विद्यार्थियों के सामने शिक्षा के अनेक नए विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। व्यवसाय, अर्थशास्त्र, वित्त, संगणक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और जैवचिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम आरंभ होने की संभावना है। आधुनिक तकनीक और शोध से जुड़े विषयों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव विद्यार्थियों को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप तैयार करने में सहायक हो सकता है। हालांकि प्रत्येक संस्थान के पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क और शैक्षणिक सत्र की जानकारी अलग-अलग होगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने का एक प्रमुख लाभ यह हो सकता है कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विदेश नहीं जाना पड़ेगा। विदेश में अध्ययन के दौरान यात्रा, आवास और जीवनयापन पर होने वाले खर्च की तुलना में भारत में अध्ययन करना कुछ परिवारों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने परिवार और सामाजिक परिवेश के निकट रहते हुए नई शैक्षणिक पद्धतियों से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा।

फिर भी यह मान लेना उचित नहीं होगा कि विदेशी विश्वविद्यालयों की भारतीय परिसरों में शिक्षा अनिवार्य रूप से सस्ती होगी। वास्तविक आर्थिक लाभ संस्थान के शुल्क, छात्रवृत्ति, आवास व्यवस्था और पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर करेगा। यदि शुल्क अत्यधिक हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और सामान्य आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों की पहुँच सीमित रह सकती है। इसलिए शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की सफलता का मूल्यांकन केवल विश्वविद्यालयों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को कितने अवसर प्राप्त हुए।

विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने भी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। उन्हें शिक्षण की गुणवत्ता, शोध सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रमों के विकास और उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा का लाभ तभी व्यापक होगा जब सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में अनेक उत्कृष्ट संस्थान पहले से मौजूद हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और विभिन्न शोध संस्थान देश की शैक्षणिक क्षमता के महत्त्वपूर्ण आधार हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते समय भारतीय संस्थानों की उपलब्धियों और स्वायत्तता को समान महत्त्व दिया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य केवल विदेशी ज्ञान को अपनाना नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, भाषाओं, संस्कृति और अनुसंधान को विश्व के सामने प्रस्तुत करना भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए चार प्रमुख दिशाओं पर बल दिया है। इनमें विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक और शोध सहयोग, विदेशी विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन के लिए आकर्षित करना, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की सुविधा देना और भारतीय संस्थानों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यह दृष्टिकोण शिक्षा को एकतरफा आदान प्रदान के स्थान पर पारस्परिक सहयोग का माध्यम बनाता है।

इस दिशा में भारतीय संस्थानों की विदेशी उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जांजीबार में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने दुबई में अपने परिसर स्थापित किए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि भारत केवल विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने वाला देश नहीं है, बल्कि स्वयं भी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित कर रहा है।

विदेशी परिसरों के विस्तार के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि संबंधित संस्थान को किस प्रकार की अनुमति प्राप्त है, उसके पाठ्यक्रम की मान्यता क्या है और कुल शुल्क कितना होगा। शिक्षकों की योग्यता, प्रयोगशालाओं की उपलब्धता, छात्रावास की सुविधा और उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई संस्थान बीच में अपना संचालन बंद कर दे तो अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। शुल्क वापसी, शिकायत निवारण और पाठ्यक्रम परिवर्तन की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। नियामक संस्थाओं को समय समय पर शैक्षणिक गुणवत्ता की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे प्रतिष्ठित नामों के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निराशा का सामना न करना पड़े।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का विस्तार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। इससे विद्यार्थियों को विविध पाठ्यक्रम, शोध के नए अवसर और अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय संस्थानों को भी अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

इस परिवर्तन की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समाजोपयोगी बनती है। भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की आकांक्षा तभी सार्थक होगी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा कुछ संपन्न परिवारों तक सीमित न रहकर व्यापक विद्यार्थी समुदाय के लिए उपलब्ध हो। शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर समान अवसर, ज्ञान के आदान प्रदान और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बने, यही समय की आवश्यकता है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों की छुट्टी बचाने वाला 18 वर्षीय 'सरकारी ठेकेदार'

-सचिन कुमार गौतम

लाखों का वेतनमान और सरकारी नौकरी के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं उठाकर चंद घंटे काम करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी और तकनीकी जानकार जो काम नहीं कर सके, उसे एक 18 साल के लड़के ने संभव कर दिखाया है। यह काम है लाखों-करोड़ों नाम वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने की तकनीकी सुविधा। अमूमन वोटर लिस्ट की लाखों पन्नों वाली स्कैन पीडीएफ फाइलों में एक नाम खोजने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब रांची के 18 साल के एथिकल हैकर सार्थक सिद्धांत ने उत्तर प्रदेश की 6.8 लाख पीडीएफ फाइलों को डिजिटल डेटा में बदलकर इसे आसानी से खंगालने वाला बना दिया है।

मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्थक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने चुनाव आयोग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश की सभी वोटर लिस्ट की पीडीएफ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे स्कैन की गई फाइलों में मौजूद नाम और दूसरी जानकारियां मशीन से पढ़े जा सकने वाले डेटा में बदल गई।

दरअसल, अब तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ज्यादातर वोटर लिस्ट पीडीएफ के रूप में थीं। ऐसे में किसी शख्स का नाम तलाशने के लिए पहले विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग बूथ की जानकारी जुटानी पड़ती थी। इसके बाद उससे जुड़ी पीडीएफ डाउनलोड कर उसके पन्नों को एक-एक करके देखना होता था। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली थी, बल्कि आम नागरिकों के लिए तकनीकी रूप से भी कठिन थी।

सार्थक की टीम ने ओसीआर तकनीक की मदद से इन स्कैन फाइलों को टेक्स्ट और टेबल के रूप में व्यवस्थित किया। अब किसी खास रिकॉर्ड को खोजना और अलग-अलग चुनावों या रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में हुए बदलावों की तुलना करना आसान होगा। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची, एसआईआर की दोनों सूचियां और 2027 का मसौदा शामिल है।

सार्थक के मुताबिक उनकी टीम ने कुल 6.8 लाख पीडीएफ फाइलों को प्रोसेस किया, जिनमें ज्यादातर स्कैन की गई थीं। इनसे निकाले गए डेटा को 54.8 करोड़ पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए अलग-अलग टेबल तैयार की गई हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र का डेटा अलग से देखा जा सकता है।

सार्थक के मुताबिक सार्वजनिक रूप से डाउनलोड किए जा सकने वाले डेटा में निजता का भी ध्यान रखा गया है। इसमें वोटर के नाम, रिश्तेदारों के नाम, एपिक नंबर और मकान नंबर जैसे संवेदनशील पहचान संबंधी विवरणों को एक टोकन से बदल दिया गया है। इसका मकसद यह है कि डेटा खुला हो, लेकिन व्यक्तिगत पहचान का दुरुपयोग न हो सके।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आम नागरिक, पत्रकार, शोधकर्ता और चुनावी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा को समझ सकते हैं। वोटर सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने जैसे मुद्दों पर बेहतर जांच संभव हो सकती है। साथ ही, अलग-अलग संशोधन चक्रों की तुलना से यह भी देखा जा सकता है कि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची में क्या परिवर्तन हुए हैं।

दरअसल, विपक्ष चुनाव आयोग से इस तरह की व्यवस्था की मांग पहले से करता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को 2027 की ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में जानकारी खोजने और डाउनलोड करने लायक पीडीएफ फाइलें उपलब्ध कराई थीं।

हालांकि, सार्थक ने इससे आगे का भी काम किया है। उन्होंने मतदाता सूची के चार सेट्स को एक साथ लाकर लाखों डॉक्यूमेंट्स को एक डेटासेट बनाया है। इससे न केवल नाम खोजना आसान हुआ है, बल्कि विभिन्न समयों में जारी सूचियों की तुलना भी संभव हुई है। यही कारण है कि इस पहल को लोकतांत्रिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस काम के लिए सार्थक सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए लिखा कि सार्थक का यह काम लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन बेहद आवश्यक है। गोगोई के अनुसार, जब नागरिक सतर्क रहते हैं और जनता की सेवा के लिए बने संस्थानों की जांच-पड़ताल होती है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

कांग्रेस सांसद के अलावा भी कई और लोगों ने सार्थक सिद्धांत के काम को जरूरी और सराहनीय बताया है। हालांकि, अब तक भाजपा या चुनाव आयोग की तरफ से सार्थक की तारीफ में कोई बयान पढ़ने को नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने भी अभी तक उनके इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

खैर, सार्थक का यह पहला कारनामा नहीं है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने उन्हें सौ प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं में शुमार किया है। पत्रिका हर साल ऐसे 100 उभरते भारतीय युवाओं की सूची जारी करती है, जो अपने काम, नए आइडिया और उपलब्धियों से देश का भविष्य गढ़ने में भूमिका निभा रहे हैं।

दरअसल, मई महीने में सार्थक सिद्धांत तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में गड़बड़ियों को उजागर किया था। उन्होंने कम अंक मिलने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी और बोर्ड के नई चेकिंग सिस्टम की पड़ताल शुरू की। इसमें उन्हें कई खामियां नजर आई।

इसके बाद ही ओएसएम को लेकर देशभर के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी आवाज उठाई थी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी जवाबदेही के सवाल खड़े किए। सार्थक की इस पहल ने उन्हें एक ऐसे युवा के रूप में स्थापित किया, जो सिर्फ समस्या पहचानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाधान भी खोजता है।

इसके बाद जून में सार्थक ने भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स निकालकर एक पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया था। तब एक्स पर उन्होंने अपनी पोस्ट में बड़ी ही साफगोई से लिखा, 'पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए जिस तक सबकी आसानी से पहुंच हो। आज से ऐसा ही है।'

सार्थक ने बताया था कि दो हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सरकार के सीपीपी पोर्टल से लगभग 1.66 करोड़ खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड्स निकाले हैं। अब ये तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स आम नागरिकों, पत्रकारों और रिसर्चर्स के लिए पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में खंगालने के लिए मौजूद हैं। सार्थक का मकसद है कि लोग इस डेटाबेस को डाउनलोड करें और अपने स्तर पर इन सरकारी रिकॉर्ड्स की जांच-पड़ताल करें। इसे उन्होंने पारदर्शिता की तरफ एक कदम बताया था।

सार्थक जैसे युवाओं को देखकर उम्मीद बंधती है कि देश में न प्रतिभाशाली युवाओं की कमी है, न नेक इरादों से काम करने का जज्बा उनमें कम है। देशभक्ति केवल नारे लगाने से ही साबित नहीं की जाती है, कई बार व्यापक हितों को ध्यान में रखकर चुपचाप सही तरीके से काम करना भी देशसेवा ही है।

सार्थक की तरह तकनीकी ज्ञान से संपन्न कई और युवा देश में मौजूद होंगे, जिन्हें सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराना चाहिए ताकि वे ऐसे ही बड़े काम कर दिखाएं, जो असल में सरकारी दफ्तरों और विभिन्न आयोगों में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को करने चाहिए। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि तकनीक और जनता की पहुंच को जोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है।

यह पहल यह भी दिखाती है कि सरकारी डेटा को सिर्फ फाइलों और पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। उसे इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि आम नागरिक आसानी से उसका उपयोग कर सकें। सार्थक सिद्धांत के काम ने यह सवाल खड़ा किया है कि जब एक 18 साल का छात्र इतना बड़ा डेटा व्यवस्थित कर सकता है, तो संसाधन और अधिकार रखने वाले सरकारी तंत्र को ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए?

आने वाले समय में यही उम्मीद की जाएगी कि चुनाव आयोग और अन्य सरकारी संस्थाएं ऐसी पहलों को सकारात्मक रूप से लें और डेटा की पहुंच को और अधिक सरल बनाएं। इससे न केवल नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।

क्या राहुल-अखिलेश कर पाएंगे चक दे ! इंडिया

- सर्वमित्रा सुरजन

इस बीस साल पुरानी फिल्म का यह दृश्य अभी उत्तरप्रदेश चुनाव की हलचल देखकर याद आ गया। फिल्म की तरह यहां भी टीम इंडिया के सामने आर या पार वाली स्थिति है। सामने भाजपा जैसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, जिसके पास न केवल लगातार दो बार की सत्ता है, बल्कि इस समय तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पार्टी की तिजोरी में कैद है। आज देश के मंदिरों के अलावा सबसे ज्यादा संपत्ति शायद भाजपा के घोषित-अघोषित खातों में ही है।

फिल्म चक दे! इंडिया में प्रीति सभरवाल (सागरिका घाटगे) और कोमल चौटाला (चित्राशी रावत) टीम इंडिया की मुख्य फॉरवर्ड खिलाड़ी होती हैं और दोनों के बीच सबसे ज्यादा गोल करने की होड़ रहती है। प्रीति का क्रिकेटर मंगेतर महिला हॉकी का मखौल उड़ाता है तो प्रीति खुद को साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल करना चाहती है, वहीं हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली कोमल को लगता है कि अगर वह ज्यादा गोल नहीं करेंगी, तो बड़े शहरों की खिलाड़ियों के बीच उनकी अनदेखी हो जाएगी। लिहाजा दोनों मैदान पर एक-दूसरे को गेंद (पास) देना बंद कर देती हैं, जिससे कई आसान गोल करने के मौके चूक जाते हैं। हालांकि एक निर्णायक मैच में कोमल को लगता है कि प्रीति की चुनौती उससे बड़ी है, तो वह आखिरी पलों में उसकी तरफ गेंद बढ़ा देती है, ताकि गोल हो, टीम को जीत मिले और प्रीति अपने मंगेतर को हॉकी की अहमियत साबित कर सके।

इस बीस साल पुरानी फिल्म का यह दृश्य अभी उत्तरप्रदेश चुनाव की हलचल देखकर याद आ गया। फिल्म की तरह यहां भी टीम इंडिया के सामने आर या पार वाली स्थिति है। सामने भाजपा जैसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, जिसके पास न केवल लगातार दो बार की सत्ता है, बल्कि इस समय तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पार्टी की तिजोरी में कैद है। आज देश के मंदिरों के अलावा सबसे ज्यादा संपत्ति शायद भाजपा के घोषित-अघोषित खातों में ही है। पिछले 10-15 सालों में बाकी पार्टियों को मिलने वाली चंदे की रकम कम होती गई, लेकिन भाजपा के चंदे में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। इन पैसों से पार्टी के केवल आलीशान दफ्तर नहीं बन रहे हैं, मीडिया को खरीदने से लेकर नैतिक-अनैतिक सारी रणनीतियों को सफल करने के लिए भी इसी पैसे को झोंका जाता है। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, एसआईआर के बाद ही बिहार और बंगाल दोनों में भाजपा ने सरकार बना ली है। टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, जेडीयू जितनी भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, या तो भाजपा ने उन्हें तोड़ दिया या फिर अपने साथ मिला लिया। यह सब धन के बल पर ही हुआ है। चुनाव के वक्त भाजपा अपनी मर्जी का नैरेटिव कैसे तैयार करवाती है, यह भी साल दर साल देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को यह सब नजर नहीं आ रहा होगा। बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था, तो इसी वजह से ही बना था कि तमाम विपक्षी दलों को भाजपा का खेल साफ-साफ समझ आ रहा था। उस समय जो एकता कायम हुई थी, उसका फायदा भी मिला था। लेकिन अब प्रीति सभरवाल और कोमल चौटाला की तरह सपा और कांग्रेस फिर एक दूसरे को गेंद न देकर अकेले गोल करना चाह रहे हैं।

बीते दो दिनों में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठकें हुईं, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि उनकी तरफ से अन्य प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इसमें सपा ने कांग्रेस को 403 में महज 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस कम से कम सौ सीटें चाहती है। उप्र जैसे बड़े राज्य में ज्यादा सीटों पर लड़ना और सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा हर तरह से जायज है। लेकिन केवल सपना पालने से कुछ नहीं होता, उसके लिए त्रुटिरहित रणनीति बनानी पड़ती है और भावनाओं में बहे बिना सख्ती से उसका पालन भी करना होता है। यह काम दोनों दलों के शीर्ष नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं में एक अतिरिक्त महत्वाकांक्षा पहली पंक्ति में आने की भी रहती है, जिसकी वजह से वे पार्टी या गठबंधन का दूरगामी नुकसान करवाते हैं। सपा में रामगोपाल यादव और कांग्रेस में राजेंद्र पाल गौतम या इमरान मसूद जैसे नेता फिलहाल यह काम कर रहे हैं। इनकी तरफ से अनावश्यक बयानबाजी काफी नहीं थी, जो अब अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट भी आ गई। जिसमें वे सीट नहीं जीत को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं सीट समायोजन पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप जो भी सोच रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं, उसे सार्वजनिक करने की कौन सी मजबूरी थी।

इधर सीट बंटवारे पर पेंच फंसा ही हुआ है और इस बीच सपा ने मंगलवार देर रात पांच सीटों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। क्या सपा थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती थी या फिर यह कांग्रेस पर दबाव बनाने का कोई तरीका है। अभी जो 26 सीटें कांग्रेस को प्रस्तावित की गई हैं, उनमें दो ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। बाकी 20 सीटों पर सपा का आकलन है कि कांग्रेस के लिए चुनावी संभावना हो सकती है। सपा और कांग्रेस दोनों दल अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीट बंटवारा किस आधार पर हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन था, और 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, छह पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इसे अपना मजबूत प्रदर्शन मानकर चाहती है कि कम से कम हर लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर कांग्रेस करीब सौ सीटों की मांग कर रही है। लेकिन सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को याद दिला रही है कि उस समय कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, और केवल दो सीटें जीती थीं। तब पार्टी के 387 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। जबकि तब सपा ने 111 सीटें जीती थीं। इससे पहले 2017 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में सपा को 54 और कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली थी।

लेकिन 2017 और 2022 दोनों बार जीत भाजपा की ही हुई थी। यही वह बड़ा सबक है जो अब सपा और कांग्रेस को याद रखना होगा कि चाहें अकेले लड़ें या साथ लड़ें, जीत तभी मिलेगी, जब अपने मुकाबले खड़ी पार्टी की असली ताकत को पहचानना होगा। और भाजपा की असली ताकत उसकी तिजोरी से होते हुए बूथ संभालने में लगे कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों तक है। भाजपा के अदने से कार्यकर्ता को भी पता है कि उनकी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और एक बार सत्ता में आ गए तो फायदा सबको मिलता है। सपा और कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं

गुंजन की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं और खिलाड़ियों के लिए है बड़ी प्रेरणा : नायब सिंह सैनी



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर निवास पर हांसी के ढाणा कलां गांव की होनहार मुक्केबाज गुंजन को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। गुंजन ने सेनेगल के डकार में आयोजित यूथ ओलंपिक 2026 की बॉक्सिंग स्पर्धा के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। इससे पूर्व भी गुंजन ने 2026 अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप (जकार्ता, इंडोनेशिया) और 2026 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप (बैंकॉक, थाईलैंड) में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुंजन की असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वर्णिम सफलता हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गुंजन की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हरियाणा की खेल नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी एवं खिलाड़ी-हितैषी खेल नीति के कारण आज हरियाणा देश में खेलों का पावरहाउस बन चुका है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से ही आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, नर्सरियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता राशि समय पर उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि खिलाड़ी बिना किसी चिंता के केवल अपने खेल और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मुख्यमंत्री ने गुंजन और उनके परिवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस सम्मान समारोह के दौरान हांसी के विधायक विनोद भ्याणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, खेल निदेशक शक्ति सिंह, अतिरिक्त निदेशक अश्वनी मलिक तथा गुंजन के परिजन भी उपस्थित रहे।

हरियाणा में एक आईएएस, छह एचसीएस अधिकारियों का तबादला



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक आईएएस और छह एचसीएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी और राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक निखिल गजराज को हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव का कार्यभार दिया गया है। एचसीएस अधिकारियों में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहीं निशु नी नम्रता सिंघल को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा तथा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

होडल की उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बेलीना को सहकारी चीनी मिल, पलवल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

हरियाणा रोडवेज, हिसार के महाप्रबंधक राहुल मित्तल को सहकारी चीनी मिल, पानीपत का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा सुरेश रवेश को सहकारी चीनी मिल, जींद का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव संजय बिश्नोई को जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, फतेहाबाद नियुक्त किया गया है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम के संयुक्त निदेशक रमित यादव को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की हुई बैठक

अनप्लग इंडिया

रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने संबंधित अधिकारियों व समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित व्यक्तियों को नियमों व अत्याचार अधिनियम के तहत उनकी सहायता करने में संबंधित विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की देरी न करें। पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारी आपस में तालमेल स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत, प्राप्त मामलों और पुनर्वास सुविधाएं तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता निगरानी समिति नियमानुसार नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अत्याचार अधिनियम 1989 के अधीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। डीसी ने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीड़ित परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए संबंधित गतिविधियां आयोजित कर जागरूकता कार्यक्रम करवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमों में समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार ने बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के तहत प्राप्त 2026-27 में 45 पीड़ितों को 74 लाख 56 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर डीएसपी संजीव, डीडीए मनोज कुमार, सहायक निशा यादव, एडवोकेट शंकर सिंह, पार्षद गीता और सरोज आदि मौजूद रहे।

रेवाड़ी में 29 नवंबर को आयोजित होगा '100वां फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल' कार्यक्रम-डीसी अभिषेक मीणा के निर्देशानुसार मेरा युवा भारत, रेवाड़ी द्वारा जिला प्रशासन रेवाड़ी के सहयोग से 29 नवंबर 2026 (रविवार) को प्रातः 7:30 बजे '100वां फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन एवं युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में फिटनेस एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम को 'नशा मुक्त युवा - विकसित भारत' अभियान के सप्ताह-11 से भी जोड़ा गया है। इस दौरान प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाएगी तथा नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में साइकिल रैली के साथ-साथ योग, जुंबा एवं अन्य फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और आमजन को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरा युवा भारत, रेवाड़ी एवं जिला प्रशासन रेवाड़ी की ओर से रेवाड़ी जिले के सभी नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों, युवा क्लबों एवं साइकिलिंग प्रेमियों से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और स्वस्थ, नशा मुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

जनसंवाद और सीएम विंडो की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर करें समाधान : भोपाल सिंह खदरी



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष सुनवाई के लिए आती हैं। ऐसे में सभी विभागों के अधिकारी इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत के निस्तारण के बाद प्रार्थी की संतुष्टि के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति (प्रोमिनेंट पर्सन) से भी समाधान का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ जनसंवाद एवं सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने उच्चतर शिक्षा विभाग, जिला नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), विभिन्न विश्वविद्यालयों, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहरी संपदा विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग तथा हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों की शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खदरी ने कहा कि जनसंवाद एवं सीएम विंडो की प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा के लिए शुरू किए गए प्रथम चरण के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतों के समाधान की स्थिति में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में शिकायत निवारण का स्कोर बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो विभिन्न विभागों के लिए संतोषजनक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी शिकायतकर्ताओं से सीधे दूरभाष पर बातचीत कर उनकी संतुष्टि की जानकारी ली जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय का नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का फीडबैक लेना वर्तमान सरकार की एक सराहनीय पहल है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनवरी माह में सीएम घोषणाओं और जनसंवाद से संबंधित शिकायतों की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। इसलिए सभी नोडल अधिकारी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालयों की 525 शिकायतें लंबित, शीघ्र कार्रवाई के निर्देश

सिरसा विश्वविद्यालय से संबंधित एक मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विश्विद्यालय द्वारा वर्ष 2008 में नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दे दिया गया है, जबकि उसकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2006 को हुई थी। इस पर ओएसडी ने संबंधित मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों की स्थिति की जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि कुल 749 शिकायतों में से 77 का समाधान किया जा चुका है तथा 62 शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। शेष 525 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। दोबारा नहीं खोली जाएंगी शिकायतें, असंतुष्ट प्रार्थी दर्ज करवा सकेंगे नई शिकायत

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की शिकायतों की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने बताया कि विभाग की कई शिकायतें दोबारा खोली गई हैं। इस पर श्री खदरी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार अब किसी भी शिकायत को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी समस्या के संबंध में अलग से नई शिकायत दर्ज करवा सकते है।

सिंचाई विभाग की जनसंवाद 1098 समस्याएं तथा सी एम विंडो की 361 समस्याओं की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा कृषि विभाग में रबी बाजरा फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर लंबित मुआवजा राशि को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की जनसंवाद की 81 व सी एम विंडो की 991 समस्याओं की समीक्षा की गई।

भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े मामलों में कार्रवाई के निर्देश

पंचकूला के मानकपुर, सुखोमाजरी और रामगढ़ के निवासियों की शिकायतों की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने बताया कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिया जा चुका है, जबकि शिकायतकर्ता जिला न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

इसी प्रकार सोनीपत निवासी कृष्णा की शिकायत पर ओएसडी ने संबंधित नोडल अधिकारी को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से जुड़े मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

रोहतक में चार लोगों की हत्या, हरियाणा की कानून व्यवस्था पर जवाब दे भाजपा सरकार : कुमारी सैलजा

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने रोहतक में एक ढाबे पर गोलीबारी में चार लोगों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। सांसद ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस वारदात ने एक बार फिर हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या, फिरौती और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों का दुस्साहस बढ़ रहा है और आम नागरिकों को अपनी जान की चिंता है। सांसद ने सवाल किया कि लगातार सामने आ रही इन वारदातों के बावजूद भाजपा सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? आखिर सरकार ने हरियाणा को किस हाल में पहुंचा दिया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? सांसद ने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों को फिरौती की धमकियां मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। सरकार बताए कि ऐसी शिकायतों पर कितने मामलों में कार्रवाई हुई और धमकी मिलने के बाद पीड़ितों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए। सांसद ने कहा कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।

कुमारी सैलजा ने मांग की कि रोहतक की वारदात की जांच तेजी से पूरी की जाए और हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सांसद ने मृतकों के परिवारों को उचित सहायता देने की भी मांग की। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में विफल रही है। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करें और सार्वजनिक रूप से बताएं कि हत्या, फिरौती और गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

देहरादून में 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल हुई उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा

संविधान दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल हुई। सांसद ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाया और पूछा कि जब जनता का वोट ही नहीं बचेगा, तो संविधान कैसे बचेगा? सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान, लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संघर्ष जारी रहेगा। सैलजा ने कहा कि बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है।

भिवानी जिला बार के विकास के लिए सांसद धर्मबीर सिंह ने की 30 लाख रुपये देने की घोषणा, पहले भी दे चुके हैं 20 लाख

अनप्लग इंडिया

भिवानी। लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने भिवानी जिला बार एसोसिएशन के विकास और अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 30 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने इससे पहले भी अपनी सांसद निधि से जिला बार के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए थे। इस तरह बार एसोसिएशन के विकास के लिए सांसद की ओर से अब तक कुल 50 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी है। सांसद धर्मबीर सिंह जिला बार कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। जिला बार में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए भविष्य में भी हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

नवनिर्मित न्याय द्वार का किया अवलोकन

इस दौरान सांसद ने न्यायालय के नवनिर्मित 'न्याय द्वार' गेट नंबर-1 का विशेष रूप से अवलोकन किया। उन्होंने बार परिसर में हुए निर्माण कार्यों को देखा और बार प्रधान युधिष्ठिर वत्स द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला बार में सुविधाओं का विस्तार अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। सांसद की ओर से अतिरिक्त 30 लाख रुपये देने की घोषणा के बाद बार परिसर में विकास कार्यों को गति मिलने और आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ी है।

ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में पेरिस इंटरनेशनल ओलंपिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज



विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भी अधिवक्ताओं के साथ संवाद में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान युधिष्ठिर वत्स, वरिष्ठ अधिवक्ता सोहन लाल मक्कड़, अविनाश सरदाना, बी.बी. जैन, ब्रह्मानंद, कांति चन्द्र कौशिक, बजरंग लाल शर्मा, अरविंद शर्मा, नीरज भारद्वाज, राजेश तंवर, मनमोहन भूरटाना, संजय सोनी, सुमित जांगड़ा, राजीव गौड़, सुरेश मेहता, शमशेर दहिया, राजेंद्र वर्मा, परमहंस चोपड़ा, केंद्र मनी, कुलदीप शर्मा, महेश भारद्वाज, श्रीकांत भारद्वाज, मनीष चौहान और रोशन लाल शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।

घर के समीप बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : आरती सिंह राव

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को घर के समीप बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) तथा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचयू) का सुदृढ़ीकरण करने से आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को और अधिक मजबूत करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करनाल के पोपरा, उपलाना और जलमाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा यमुनानगर के चमरोड़ी में उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्रताप नगर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्यों की संशोधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 170.32 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है ताकि इन परियोजनाओं को और अधिक गति मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण



कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही इन स्वास्थ्य संस्थानों का लाभ मिल सके। इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों से ये संशोधित रफ कॉस्ट एस्टिमेट प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थल की आवश्यकताओं और संशोधित लागत आकलनों के आधार पर संबंधित जिला परिषदों के कार्यकारी अभियंताओं द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर जिले के एसएचसी चमरोड़ी के निर्माण कार्य के लिए पूर्व में जारी 55.50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के मुकाबले संशोधित लागत 88.71 लाख रुपये आंकी गई है, जिसके लिए 33.21 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति अपेक्षित है। इसी प्रकार यमुनानगर के ही सीएचसी प्रताप नगर स्थित बीपीएचयू के लिए पूर्व में 50.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसकी संशोधित लागत 55.85 लाख रुपये होने पर 5.85 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त करनाल जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत पीएचसी पोपरा के निर्माण कार्य के लिए 424.67 लाख रुपये की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के मुकाबले संशोधित लागत 467.01 लाख रुपये हो गई है, जिसके लिए 42.34 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। वहीं पीएचसी उपलाना के लिए 418.71 लाख रुपये की पूर्व स्वीकृति के स्थान पर संशोधित लागत 476.01 लाख रुपये होने से 57.3 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति तथा पीएचसी जलमाना के लिए 435.18 लाख रुपये की पूर्व स्वीकृति के मुकाबले संशोधित लागत 466.80 लाख रुपये होने पर 31.62 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता बताई गई है।

चालानों की राशि से गुड़गांव की सड़कें बनवाकर जनता पर उपकार कर दे पुलिस: पंकज डावर

गुड़गांव। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने गुड़गांव पुलिस द्वारा पिछले 45 दिनों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के 6 लाख 83 हजार 495 चालान काटकर 140 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने पर कहा कि चालान की इस विशाल राशि को पुलिस जनहित में ही खर्च करे। शहर में अनेक स्थानों पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन सड़कों का निर्माण पुलिस कराए। यह गुड़गांव की जनता पर पुलिस का उपकार और पुण्य का काम होगा। पंकज डावर ने कहा कि आज गुड़गांव की जनता का विश्वास सरकार, जीएमडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन से पूरी तरह उठ चुका है। जिस शहर को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, स्मार्ट सिटी जैसे बड़े-बड़े नाम दिए गए, उसकी सड़कों की हालत देखकर लगता है कि यह शहर नहीं, बल्कि गड्ढों का शहर बन गया है। हर चौक-चौराहे पर, हर सेक्टर की सड़क पर, हर गांव के रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बरसात में ये गड्ढे तालाब बन जाते हैं और सूखे में धूल और मिट्टी से लोगों का जीना दूभर हो जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार हर साल सड़कों के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये के बजट की घोषणा करती है, टेंडर होते हैं, ठेके दिए जाते हैं, लेकिन सड़कें बनने के बजाय कागजों में ही बन जाती हैं। जीएमडीए और नगर निगम के अधिकारी सिर्फ फाइलों में सड़कें बनाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखता। जिला प्रशासन भी सिर्फ बैठकों और निरीक्षणों तक सीमित रह गया है। जनता शिकायत कर-कर के थक चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

डावर ने गुड़गांव पुलिस से मांग की कि पुलिस जनसहयोगी बनकर आगे आएं और इस चालान की राशि से शहर की टूटी सड़कों का निर्माण कराए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर भी देखा जाता है कि कई जगह पुलिस ही सड़कों के गड्ढे भरती है, बैरिकेड लगाती है, ट्रैफिक संभालती है। जब पुलिस गड्ढे भर सकती है तो सड़कें भी बनवा सकती है। पुलिस को इस पुण्य के काम में आगे आना चाहिए। पंकज डावर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जीएमडीए के पास मास्टर प्लान हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जनता को चलने के लिए एक साफ-सुथरी सड़क नहीं बनाई जा रही।

पी.एम. श्री. जी.एस.एस.एस. में मंडल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता धूमधाम से संपन्न

अनप्लग इंडिया

करनाल। नीलोखेड़ी स्थित पी.एम. श्री. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जी.एस.एस.एस.मंडल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में संसदीय प्रणाली की समझ विकसित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और उनमें नेतृत्व व तर्क क्षमता को निखारना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या जसमीत कौर, प्रधानाचार्य विजय भारद्वाज, अंजना शर्मा तथा बजाज की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवा संसद जैसे आयोजन छात्रों को देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नीति निर्माण की प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर देते हैं। प्रतियोगिता का मूल्यांकन करने के लिए गठित निर्णायक मंडल में डा. जय सिंह, डॉ अनिल कुमार, डॉ निर्मल सिंह शामिल रहे,



जिन्होंने प्रतिभागियों के प्रस्तुतीकरण, तथ्यों की स्पष्टता और संसदीय मर्यादा के पालन के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन किया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय और शिक्षा विभाग की टीम ने अहम भूमिका निभाई। आयोजकों व मार्गदर्शकों में प्रधानाचार्या रजनी वर्मा, बृजेश वत्स (डाइट शाहपुर) शशि चौधरी (पीजीटी राजनीति विज्ञान), सुषमा गुप्ता (पीजीटी राजनीति विज्ञान), डॉ. अंजलि शर्मा (पीजीटी मनोविज्ञान), सुभाष मलिक (पीजीटी इतिहास) तथा अंबुज कुमार पीजीटी भूगोल शामिल रहे। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह लेक्चर इंग्लिश, रामफल लेक्चर स्टेनो, रिचा पीजीटी वाणिज्य, अरुण कुमार, दिनेश, पिंकी का विशेष सहयोग भी सराहनीय रहा। तन्वी विपक्ष नेता, वंश प्रधानमंत्री, तमन्ना अध्यक्ष, भूमिका गृहमंत्री, नीतू शिक्षा मंत्री, जयपाल विपक्ष नेता,

मोहित पेट्रोलियम मंत्री, आंचल विपक्ष नेता, सत्यम कृषि मंत्री, अंजलि विपक्ष नेता, सिम्मी विपक्ष नेता की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही।

संक्षिप्त डायरी

अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ बल्ला घुमाएंगे अलीगढ़ के पुष्कर

अनप्लग इंडिया

अलीगढ़। सुपर 90 लीग में हरियाणा वॉरियर्स की टीम में हुआ चयन, क्रिस गेल और शिखर धवन जैसे दिग्गज भी दिखेंगे अलीगढ़। जिले के ईसेपुर निवासी क्रिकेटर पुष्कर शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान को नई ऊंचाई दी है। उनका चयन केन्या में होने वाली प्रतिष्ठित सुपर 90 लीग सीजन-4 के लिए हरियाणा वॉरियर्स की टीम में हुआ है। तीन दिसंबर से नैरोबी में शुरू होने वाली इस लीग में पुष्कर दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटरों के साथ मैदान साझा करेंगे। प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, भारत के शिखर धवन, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हरियाणा वॉरियर्स में मार्टिन गुप्टिल, वेन पार्नेल, एंजेलो मैथ्यूज और रवि बोपारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी होगी। लीग में सात फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का भारत समेत कई देशों में सीधा प्रसारण होगा। भारत में दर्शक जियोहॉटस्टार पर मैच देख सकेंगे। पुष्कर इससे पहले केन्या की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय लीग में चयन को उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी इस सफलता से ईसेपुर सहित अलीगढ़ के खेल जगत में खुशी है। परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।

दयाशंकर सिंह के खिलाफ फिर गिरफ्तारी वारंट जारी, कोतवाली में अभद्रता का मामला

अनप्लग इंडिया

बलिया। कोतवाली में अभद्रता के मामले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जबकि इसी मामले में अदालत ने एमएलसी रविशंकर सिंह की गैरहाजिरी माफ कर दी। बलिया जिले की कोतवाली में घुसकर तत्कालीन कोतवाल सर्वजीत शाही के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने के मामले में सीजेएम शैलेष पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह की गैरहाजिरी माफ कर दी। वहीं, सह अभियुक्त सदर विधायक एवं परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अदालत ने सदर कोतवाल को वारंट तामील कराने का आदेश देने के साथ ही जमानतदारों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। अभियोजन के मुताबिक, घटना चार दिसंबर 2003 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे कोतवाली परिसर में हुई थी। आरोप है कि रविशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह करीब 20 समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे थे। सूचना मिलने पर तत्कालीन एसएचओ सर्वजीत शाही वहां पहुंचे तो उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की गई। आरोप है कि इस दौरान उनका कॉलर भी पकड़ा गया। एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता की गई थी। एमएलसी रविशंकर सिंह अदालत में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा चुके हैं। इसी आधार पर बृहस्पतिवार को उनकी गैरहाजिरी माफ कर दी गई। वहीं, मंत्री दयाशंकर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ पुनः एन-स्टेप गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही वारंट की तामील सदर कोतवाल के माध्यम से कराने और जमानतदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

मैदागिन से सोनारपुरा तक बनेगा नो व्हीकल जोन, चलेंगे 40 गोल्फ कार्ट

अनप्लग इंडिया

वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मार्ग जाम मुक्त बनाने की तैयारी है। मैदागिन से सोनारपुरा तक नो व्हीकल जोन बनेगा। इस रूट पर 40 गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी है। मैदागिन से सोनारपुरा के बीच रोजाना 2500 से अधिक वाहनों के दबाव और जाम से निजात दिलाने के लिए पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन बनाने की तैयारी है। इस क्षेत्र में निजी कार, ऑटो, रिक्शा और ई-रिक्शा की आवाजाही बंद कर केवल ई-गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है। इसके लिए नगर निगम ने टोयोटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से 40 गोल्फ कार्ट मांगे हैं। टोयोटा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत भी हो चुकी है। प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इससे श्री काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ मैदागिन से सोनारपुरा के बीच रहने वाले व्यापारियों को भी लाभ होगा। व्यापारियों के पास बनाए जाएंगे। इस सुविधा के लिए यात्री को निश्चित शुल्क देना होगा। यह कदम भक्तों और यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उठाया जा रहा है। पिछले दिनों अक्षय तृतीया से राजनारायण पार्क (बेनियाबाग), मैदागिन समेत कई स्थानों पर 16 गोल्फ कार्ट की सुविधा शुरू की गई है। मैदागिन, राजनारायण पार्क और कबीर चौरा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक गोल्फ कार्ट जा रही है। अभी 16 गोल्फ कार्ट चल रहे हैं। जाएगी कांग्रेस; सुप्रिया सुले के बयान का आनंद दुबे ने किया समर्थन गोल्फ कार्ट सेवा सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक है। गोल्फ कार्ट दो तरह के हैं। एक कार्ट में 9 लोगों की बैठने की क्षमता है, जबकि दूसरे में 13 लोगों के बैठने की क्षमता है। बेनियाबाग से मंदिर के गेट नंबर चार जाने वालों से 20 रुपये और गिरिजाघर से मंदिर जाने वालों से 10 रुपये लिए जा रहे हैं। 18 बार गोदौलिया के आसपास का क्षेत्र रहा नो व्हीकल जोन इस साल 18 बार गोदौलिया के आसपास का क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहा है। मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, सावन, महाशिवरात्रि, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा स्नान, डाला छठ के अलावा वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखकर इसे नो व्हीकल जोन बनाया जाता है। बाद में पूर्ववत व्यवस्था लागू होती है। इससे मैदागिन से सोनारपुरा का पूरा इलाका अक्सर जाम की चपेट में रहता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाने पर विचार चल रहा है। पिछले दिनों टोयोटा के अधिकारी काशी आए थे। उनसे बातचीत की गई है वे अपने सीएसआर फंड से गोल्फ कार्ट दें तो मैदागिन से सोनारपुरा के इलाके को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। इसमें केवल गोल्फ कार्ट चलेंगे। इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है।

यहां खतरा है, मत आना चेतावनी नजरअंदाज करना पड़ा भारी, मुंबई से चल रहा था नशे का नेटवर्क

अनप्लग इंडिया

कानपुर। कानपुर के कोकाकोला क्रॉसिंग से पुलिस ने डी-2 गैंग के मृत बदमाश सईद नाटे की पत्नी निक्की और उसके सहयोगी फैसल को 10 करोड़ रुपये की चरस समेत दबोचा है। मुंबई में रहकर गिरोह चला रही निक्की नेपाल से सस्ते दामों में मादक पदार्थ खरीदकर यूपी के रास्ते अजमेर शरीफ होते हुए मुंबई सप्लाई करने की तैयारी में थी। कानपुर में हिस्ट्रीशीटर और डी-2 गैंग के सदस्य रहे सईद नाटे की पत्नी निक्की उर्फ साजिया सिद्दकी और साथी फैसल को पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोकाकोला क्रॉसिंग के पास से 10 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह कर्नलगंज निवासी हैं। चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव के अनुसार, निक्की ने बताया कि वह नेपाल से प्राइवेट बस से 25-30 लाख रुपये में चरस लेकर मुंबई जा रही थी। वह और उसका गिरोह बसों और ट्रेनों से ही सफर करता है। डीसीपी ने बताया कि निक्की फिलहाल मुंबई में रहती है और वहीं से अपने बेटे और बेटी के साथ चरस का धंधा करती है। वह बड़ी मात्रा में चरस खरीदने और बेचने के लिए गिरोह के गुर्गों के साथ खुद ही निकलती है। नाटे की हत्या के बाद निक्की ने संभाला तस्करी का धंधा निक्की ने बताया कि पति सईद नाटे 2012 में पार्षदी के चुनाव की तैयारी कर रहे थे तभी उनके दुश्मनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बच्चे छोटे होने से घर के बाहर परचून की दुकान खोली लेकिन आमदनी कम और खर्चा अधिक होने के कारण दुकान बंद करनी पड़ी।

अंडर 16 क्रिकेटर की मौत, भाई से कहता था अश्वनी... रिंकू सिंह की तरह आईपीएल खेलूंगा

अनप्लग इंडिया

हाथरस। हाईवे हादसे में अंडर-क्रिकेटर अश्वनी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर उसके बड़े भाई के आंसू नहीं रूक रहे थे। रोते-रोत हुए बोल रहे थे कि अश्वनी कहता था कि रिंकू सिंह की तरह आईपीएल खेलूंगा और जब मुझे टीवी पर देखा करोगे। हाथरस पोस्टमार्टम हाउस पर बदहवास अश्वनी के बड़े भाई टिंकू ने रोते हुए कहा कि उनके भाई ने टीवी पर आने का वादा किया था। कहता था कि रिंकू सिंह की तरह आईपीएल खेलूंगा और जब मुझे टीवी पर देखा करोगे। वहां मौजूद अश्वनी के पूर्व कोच



राहुल व सौरभ चंद्रा ने रुंधे गले से बताया कि अंडर-16 में उसके जोड़ का कोई खिलाड़ी नहीं था। हाल ही में वह उत्तराखंड में टूर्नामेंट खेलकर आया था, जहां उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सौरभ चंद्रा ने बताया कि दो दिन पहले ही उसकी एकेडमी का हमारे साथ मैच था। उसमें भी वह अच्छा खेला था। अश्वनी के दोस्त व साथी खिलाड़ी भी पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद रहे। सभी की आंखें नम थीं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। हादसा भीषण था। ई-टेंपो होने के बावजूद ई-रिक्शा तेज रफ्तार में था। अचानक टाटा-407 के सामने आने के कारण चालक ने बचने का प्रयास किया। इधर, अश्वनी का बायां हिस्सा थोड़ा बाहर निकाला हुआ था। वह सीधे मेटाडोर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। चेहरे से लेकर पेट तक बायां हिस्सा न होने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। भानू व वैभव से मिली जानकारी पर जब भाई व साथी खिलाड़ी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो उन्होंने जर्सी पर लिखे अश्वनी, 10 नंबर और लोअर से पहचान की। इसके बाद चीख-पुकार नहीं रुकी। कोच राहुल ने बताया कि 11 साल की उम्र में अश्वनी उनके पास क्रिकेट सीखने आया था। तब वे बागला कॉलेज के मैदान में प्रैक्टिस कराते थे। बचपन से ही वह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से प्रेरित था, इसलिए उसने जर्सी नंबर 10 का चयन किया था। सौरभ चंद्रा ने बताया कि वह रिंकू सिंह क्रिकेट ग्राउंड, अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम, एडीसीए क्रिकेट ग्राउंड, विलिंगडन पवेलियन आदि मैदान पर खेल चुका था। वह रिंकू सिंह से भी मिल चुका था। छह महीने पहले ही उसने अलीगढ़ में भीकमपुर एस्टेट एकेडमी ज्वाइन की थी। खेल के जुनून पर पिता सुरेंद्र कुशवाहा अक्सर अश्वनी को टोकते थे, लेकिन भाई टिंकू उसका पक्ष लेते हुए खेलने के लिए प्रेरित करता था। किताबें पढ़ने से सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ताप्रीमियम दूसरा पहलूः किताब पढ़ने का दिमाग पर क्या असर पड़ता है? शोध में सामने आए सहानुभूति और बेहतर सोच के फायदे बस या ट्रेन से ही लौटते थे खिलाड़ी हाथरस से करीब 10 खिलाड़ियों का ग्रुप था, जो अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अश्वनी कक्षा 11वीं का छात्र था और नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ता था।

मुंबई में दबिश तो बाबूपुरवा में आ छिपे, कुछ तस्करों का मिला सुराग, जल्द होगी गिरफ्तारी

अनप्लग इंडिया

कानपुर। कानपुर मेफेड्रोन तस्करों की तलाश में मुंबई में पुलिस की दबिश के बाद तस्कर बाबूपुरवा में आकर छिप गए हैं। फजलगंज इंस्पेक्टर धनंजय कुमार का कहना है कि कुछ तस्करों का सुराग लगा है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर में मेफेड्रोन तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई के धारावी में दबिश दिए जाने के बाद वहां मौजूद रिजवान और खैय्याम के बाबूपुरवा निवासी साथी भाग निकले हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि धारावी से भागे कुछ तस्कर बाबूपुरवा के बेगमपुरवा और मुंशीपुरवा में रिश्तेदारों के घरों में छिपे हैं। तस्करों के करीबी कुछ दुकानदार यहां भी शटर बंदकर इधर-उधर हो गए हैं। पुलिस तस्करों के साथियों की तलाश में दबिशें दे रही है। पुलिस को बाबूपुरवा के हसीन, शैलू बाबा, अरबाज कट्टा आदि की तलाश है, जबकि जालौन में फैक्टरी लगाने वाले रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। अब पुलिस मेफेड्रोन की फैक्टरी लगाने वाले मास्टर माइंड मुंबई के धारावी निवासी खैय्याम की तलाश में है। फजलगंज पुलिस की एक टीम डीआरआई के साथ मिलकर मुंबई में खैय्याम के ठिकानों पर दबिशें दे रही है। सूत्रों के अनुसार दबिश के चलते 15 दिनों में खैय्याम के तीन-चार साथी वहां से भागकर बाबूपुरवा में अपने रिश्तेदारों के घरों में छिपे हुए हैं। फजलगंज इंस्पेक्टर धनंजय कुमार का कहना है कि बाबूपुरवा में छिपे कुछ तस्करों का सुराग लगा है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। परिजन बोले- ऋषभ को फंसाया गया तीन दिन पूर्व छह करोड़ की मेफेड्रोन के साथ पकड़े गए फरुर्खाबाद के जहानगंज निवासी ऋषभ ठाकुर के परिजन का कहना है कि बेटे की सराफ की दुकान है और 20 नवंबर को दुकान के काम से 60 हजार रुपये लेकर बाइक से निकला था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जानकारी हुई है। ऋषभ से जेल से मिलकर लौटे चाचा धीरज और विशाल का कहना है कि उन्हें आशंका है कि ऋषभ को फंसाया गया है। उसकी बाइक और रुपयों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है।

गंगीरी में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या, ग्राउंड में पड़ा मिला शव, छोटे भाई से पुलिस कर रही पूछताछ

अनप्लग इंडिया

अलीगढ़। भोला शराब पीकर घर आया। घरवालों से उसका झगड़ा हुआ। घरवालों ने उसे बांध दिया। रात 11 से 12 बजे के बीच वह 100 रुपये लेकर घर से चला गया। आज सुबह उसका शव ग्राउंड में मिला। गंगीरी के यादव नगर निवासी 25 वर्षीय सोनू उर्फ भोला पुत्र पप्पू की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। आज सुबह उसका शव एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भोला रात करीब 11 बजे घर से 100 रुपये लेकर निकला था। परिजनों ने बताया कि भोला शराब पीने का आदी था। कल शाम वह शराब पीकर घर आया था और घरवालों से झगड़ा कर रहा था। झगड़े के कारण घरवालों ने उसे



बांध भी दिया था। रात 11 से 12 बजे के बीच वह घर से निकला था। आज सुबह करीब 5 बजे उसका शव यादव नगर के बड़े ग्राउंड में पड़ा मिला। थाना गंगीरी अंतर्गत 27 नवंबर की सुबह यादव नगर से एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो वह शव यादव नगर निवासी भोला पुत्र पप्पू यादव का निकला । भोला के परिजनों ने बताया कि भोला कल शाम शराब पीकर घर आया था तथा घरवालों से लड़ाई-झगड़ा कर रहा था, जिस कारण से घरवालों द्वारा उसे बांध भी दिया गया था । तत्पश्चात रात करीब 11 से 12 बजे के बीच भोला अपने घर से सौ रुपये लेकर निकला था, जिसके बाद आज उसका शव यादव नगर के बड़े ग्राउंड में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है । पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।- गर्वित सिंह, सीओ (यूपी-112) घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक आर ए मनीष मिश्रा और क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।

हाशिम और मोनू को वाराणसी लाने की तैयारी

अनप्लग इंडिया

वाराणसी। नकली दवा कारोबार में वाराणसी पुलिस हाशिम और मोनू के साक्ष्य दुरुस्त करने में जुटी है। हाशिम और मोनू के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों आरोपियों को वाराणसी लाने की तैयारी है। नकली दवाओं के अंतरप्रांतीय कारोबार के मामले में रोहनिया पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसटीएफ की कार्रवाई में मुख्य सप्लायर अभिषेक सिंह, हाशिम और मोनू की गिरफ्तारी के बाद रोहनिया पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस हिमाचल प्रदेश और मेरठ से जुड़े आरोपियों को वाराणसी लाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए प्रकरण से जुड़े हाशिम और मोनू के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दोनों को वारंट बी के जरिये वाराणसी लाने के लिए साक्ष्य और जरूरी दस्तावेज दुरुस्त कर रही है। टीम को अगले 48 घंटे के अंदर निकलना था लेकिन



पुलिस दस्तावेज और साक्ष्यों को मजबूत करने के बाद अब मेरठ जाएगी साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जरूरत पड़ने पर पूछताछ करेगी।

कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में एसटीएफ मेरठ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने किराये के मकान में संचालित फैक्टरी पर छापा मारा था। यहां से दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ मेरठ में प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। इसी कारोबार से जुड़े मुख्य सरगना अभिषेक सिंह को एसटीएफ ने वाराणसी के चितईपुर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीम जल्द ही दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए मेरठ भेजी जाएगी। पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के साथ नकली दवाओं की सप्लाई से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। दस्तावेज और साक्ष्यों को मजबूत किया जा रहा है।

होश आते ही चीख पड़ी प्रियंका, डॉक्टर बोले- ठीक हैं मम्मी-पापा, उसे नहीं था पता कि उसकी दुनिया उजड़ गई

अनप्लग इंडिया

हाथरस। सासनी हाईवे हादसे में माता-पिता को खो चुकी प्रियंका को होश आया तो चीख पड़ी, डॉक्टर ने कहा मम्मी-पापा ठीक हैं। उसे पता ही नहीं था कि उसकी दुनिया उजड़ गई। मेडिकल में उसके छोटै भाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है। 12 साल की प्रियंका को जब होश आया तो स्वास्थ्यकर्मी दंपती के संबंध में बात कर रहे थे। इससे सुनकर प्रियंका चीखने और रोने लगी तो परिजनों ने यह कहकर उसे चुप कराने का प्रयास किया उसके माता-पिता ठीक हैं। उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सासनी क्षेत्र में हुए हादसे में दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी दंपती ओमकार (40) और उनकी पत्नी विनीता (36) की जान चली गई। उनकी बेटी प्रियंका और बेटे 11 साल के लक्ष्य का जेएन मेडिकल में इलाज चल रहा है।



प्रियंका के काफी चोट लगी थी, लेकिन वह बोल रही थी। उसका कहना था कि पहले माता-पिता ने बल्लभगढ़ के रास्ते मथुरा और इसके बाद हाथरस जाने की योजना बनाई थी। ट्रेन से अलीगढ़ आने के बाद बस न मिलने के कारण वह ऑटो से जा रहे थे। उसने बताया कि हादसे के बाद उसके माता-पिता बेसुध हो गए। वे और उनका भाई लक्ष्य खून से लथपथ हो गया था। तभी उसने अपने माता-पिता के संबंध में स्वास्थ्यकर्मियों के बीच चल रही बात सुनी। मामा व अन्य परिजनों के समझाने और स्वास्थ्यकर्मियों के इंजेक्शन देने के बाद वह सो गई। प्रियंका के मामा सूरज ने बताया कि उनके बहनोई ओमकार एक ट्रैक सूट व स्पोर्ट्स के कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। बृहस्पतिवार को वह परिवार के साथ पहले मेट्रो से दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे। इसके बाद वह ट्रेन से अलीगढ़ आए थे।

उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, जुटेंगे 1400 प्रतिनिधि, एक हजार संस्थानों तक पहुंचेगा तिरुक्कुरल

अनप्लग इंडिया

वाराणसी। काशी तमिल संगमम में 1400 प्रतिनिधि जुटेंगे। इसका शुभारंभ 28 नवंबर को उपराष्ट्रपति के हाथों होगा। इस दौरान सीएम योगी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। वहीं 12 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन करेंगे। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को फिर से जीवंत करने के लिए काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। 28 नवंबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी भी उद्घाटन में



शामिल करेंगे। वहीं, 12 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन करेंगे। इस बार आयोजन का केंद्र तमिल साहित्य के शास्त्रीय ग्रंथ तिरुक्कुरल की शिक्षा होगी। तमिलनाडु से करीब 1400 प्रतिनिधियों को सात समूहों में काशी लाया जाएगा। ये जानकारी बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि बीएचयू और आईआईटी मद्रास इस आयोजन के प्रमुख समन्वय संस्थान हैं। प्रतिनिधियों में विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, मीडियाकर्मी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग, पेशेवर, शिल्पकार, महिला प्रतिनिधि और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। आठ दिवसीय यात्रा के दौरान चार दिन आवागमन और चार दिन भ्रमण व विभिन्न प्रतिनिधि वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। काशी में प्रतिनिधियों को श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, बीएचयू, रामनगर किला और भारत माता मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। गंगा स्नान, गंगा आरती, शैक्षणिक संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तमिल विरासत से जुड़े विशेष भ्रमण में महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती का पैतृक आवास, काशी मठ भी शामिल हैं। आज रन फॉर काशी तमिल संगमम का आयोजन 27 नवंबर शुक्रवार को रन फॉर काशी तमिल संगमम का आयोजन होगा। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु की साझा सांस्कृतिक विरासत, भाषा, साहित्य, आध्यात्मिक परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों को एक मंच पर लाना है। इसके सुचारु संचालन और प्रतिभागियों की सहायता के लिए 1500 से ज्यादा विद्यार्थी स्वयंसेवकों का चयन किए जाने की जानकारी विश्वविद्यालय ने दी है। इस ग्रंथ की शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ने इसका अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में कराया है। इसकी बहुभाषी डिजिटल सुविधा, ऑडियो पुस्तकें, लघु फिल्में और एनिमेशन भी तैयार किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और राजमार्गों पर भी इसके दोहों को अलग-अलग भाषाओं में प्रदर्शित करने की योजना है। इसके रचयिता संत कवि तिरुवल्लुवर माने जाते हैं। इसमें कुल 1330 दोहे हैं, जिन्हें तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। काशी-तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। कन्याकुमारी से करीब 200 प्रतिनिधियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन बुधवार की दोपहर ही रवाना हो चुकी है।



कार्तिक की नई फिल्म 'कालिया' का एलान

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर एक्टर ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। कार्तिक ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है, जिसका नाम 'कालिया' है। इस बार एक्टर रोमांस या कॉमेडी करते नहीं, बल्कि राक्षसों की दुनिया में कदम रखते नजर आएंगे। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली यह फिल्म एक मॉन्स्टर थ्रिलर होगी।

कौन करेगा 'कालिया' का निर्देशन

कार्तिक की इस नई फिल्म का एलान उनके जन्मदिन के मौके पर एक डरावने वीडियो के साथ किया गया। वीडियो शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, 'श्रीकृष्ण ने उसे दूर भेज दिया था। हम इंसानों ने उसे वापस बुला लिया।' इस एक लाइन ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म का निर्देशन संदीप मोदी करेंगे, जो इससे पहले 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसी सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं।

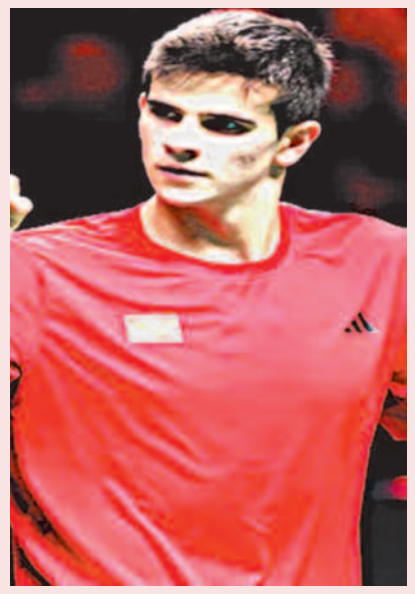
क्या होगी 'कालिया' की कहानी

'कालिया' की कहानी भारतीय लोककथाओं और पौराणिक मान्यताओं से प्रेरित होगी। फिल्म में देश के अलग-अलग हिस्सों में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और विश्वासों को आधार बनाकर एक डरावनी दुनिया तैयार की जाएगी। मेकर्स इस फिल्म में मॉन्स्टर थ्रिलर के रोमांच को भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कहानियों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि इस फिल्म के साथ धर्मा प्रोडक्शंस भी एक नए जॉनर में कदम रखने जा रहा है। अब तक रोमांटिक, फैमिली ड्रामा और कमर्शियल फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले इस प्रोडक्शन हाउस की यह पहली मॉन्स्टर थ्रिलर होगी। फिल्म को बड़े पर्दे के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि दर्शकों को एक अलग और रोमांचक सिनेमाई अनुभव मिल सके।

'कालिया' निर्देशक संदीप मोदी के लिए भी काफी खास है। 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसी सीरीज के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले संदीप अब पहली बार किसी हिंदी फिल्म के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देंगे। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ मिलकर वह एक ऐसी दुनिया रचने जा रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा में उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होगी। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा, मारिज्के डी'सूजा और कार्तिक आर्यन हैं। फिल्म 5 मई, 2028 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कार्तिक आर्यन का वर्कफ्रंट

कार्तिक आर्यन के पास आने वाले दो साल के लिए फिल्मों की लंबी लिस्ट है। एक्टर लगातार अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के जरिए दर्शकों के सामने नए अंदाज में आने की तैयारी कर रहे हैं। कार्तिक की अगली फिल्मों में फैंटेसी कॉमेडी 'नागजिला: नाग लोक का पहला कांड' शामिल है। यह फिल्म 12 फरवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा वह श्रीलीला के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म में भी नजर आएंगे, जिसकी रिलीज डेट 30 अप्रैल, 2027 तय की गई है। वहीं, कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म 'लड़ाकू' भी कार्तिक की अपकमिंग फिल्मों में शामिल है। रियल लाइफ घटनाओं से प्रेरित इस ड्रामा फिल्म के जरिए कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू करेंगे। फिल्म 18 जून, 2027 को रिलीज होगी और इसे बिरला स्टूडियोज, कबीर खान एंटरटेनमेंट और डोपामाइन स्टूडियोज मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा कार्तिक के पास 'कैप्टन इंडिया' भी है। शिमित अमीन के निर्देशन में बन रही यह एविएशन ड्रामा फिल्म एक वास्तविक रेस्क्यू मिशन से प्रेरित है। इसमें कार्तिक एक ऐसे पायलट की भूमिका निभाएंगे, जो लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशन की अगुवाई करता है। फिल्म 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।



स्पेन ने कटाया डेविस कप के सेमीफाइनल का टिकट, ऑस्ट्रिया को दी शिकस्त

बोलोग्ना (इटली), एजेंसी। स्पेन ने गुरुवार को ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर डेविस कप फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की जीत की नींव डेनियल मेरिडा ने रखी, जिन्होंने पहला मुकाबला जीतकर स्पेन को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद राफेल जॉडार ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछड़ने के बावजूद वापसी की और अपना मैच जीतकर स्पेन की टाई में जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ स्पेन ने कुल मिलाकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। एटीपी फाइनल्स में अपनी सफलता के बाद मौजूद रहे कार्लोस अल्काराज को कोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्पेन का शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आखिरी-चार का मुकाबला होना था। मेरिडा ने शुरुआती सिंगल्स मुकाबले में जोएल श्वार्जलर पर 6-4, 6-4 की शांत जीत के साथ स्पेन की जीत की नींव रखी। फिर जॉडार ने यह पक्का किया कि निर्णायक डबल्स मैच की जरूरत न पड़े, और जुरिज रोडियोनोव के खिलाफ 2-6, 6-0, 6-1 से शानदार जीत हासिल की। पहला सेट हारने के बाद 20 साल के खिलाड़ी का जवाब खास तौर पर शानदार था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए आखिरी 13 में से 12 गेम जीते। उनकी पहली सर्विस की काबिलियत अहम साबित हुई, जिसमें रोडियोनोव के साथ अपनी पहली एटीपी मीटिंग में जॉडार ने अपनी पहली डिलीवरी के बाद 94 प्रतिशत (63/67) पॉइंट जीते।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 989, निफ्टी 277 अंक गिरा

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण भी बाजार टूटा है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 989.33 अंक नीचे आकर 83,339.26 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 277.30 अंक फिसलकर 25,607.20 के स्तर पर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान, सेंसेक्स 83,208.33 के निचके स्तर जबकि निफ्टी एक



समय 25,565.90 के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। आज निफ्टी पर श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। इनमें करीब 2.5 से 5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत, बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी और इंडिगो जैसे शेयरों में तेजी आई। सेक्टरवार बात करें तो, निफ्टी आईटी इंडेक्स , रियल्टी इंडेक्स में , ऑटो और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में गिरावट आई। इसके विपरीत निफ्टी केमिकल , मेटल , मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तेजी रही। खास बात यह रही कि व्यापक बाजारों ने इस गिरावट के बीच बेहतर प्रदर्शन किया, जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में बढ़त रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सुबह सेंसेक्स 83932 और निफ्टी 25803 तक फिसले।

सोने का भाव 25 दिन में 17,000 टूटा



नई दिल्ली ।

नवंबर महीना सोने के निवेशकों और खरीदारों के लिए एक बड़े झटके या सुनहरे अवसर दोनों की तरह सामने आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर पिछले 25 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 12 फीसदी से अधिक है। वहीं, अपने जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से यह 31 फीसदी टूटकर 55,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को 1,38,485 रुपए पर बंद हुआ सोना 26 नवंबर को 1,21,478 रुपए तक गिर गया था। यानी महज 25 कारोबारी दिनों में इसकी कीमत में 17,000 रुपए से अधिक की गिरावट आई। 25 नवंबर को तो यह 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भी नीचे चला गया था, जो इस गिरावट के चरम को दर्शाता है। हालांकि, शुक्रवार को बाजार में रौनक लौटी और सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। खबर लिखे जाने तक, सोना 2,973 की बढ़त के साथ 1,25,245 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 8,339 रुपए उछलकर 1,54,182 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली।

यकीन करना मुश्किल है कि फिर सिराज को बाहर कर दिया

मोहम्मद कैफ तेज गेंदबाज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने से नाखुश

नई दिल्ली, एजेंसी। *भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर्स ने नाराजगी जताई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर कहा था और बताया था कि वह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।' वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने लिखा, 'एक बार फिर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।' मुनाफ ने अपने एक और ट्वीट में मौजूदा बॉलिंग अटैक पर भी सवाल खड़े किए।*

उन्होंने लिखा, 'चलो, कोई बात नहीं अगर आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी अगली बॉलिंग यूनिट कहां है, जो मैच जिताने में माहिर हो? '

क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अपने एक्स अकाउंट पर सिराज को लेकर लिखा, 'सिराज अब भारत के छठे रैंक वाले तेज गेंदबाज हैं। मुझे यह बहुत गलत लगता है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 विकेट लेने वालों में भारत के पास अब सिर्फ बुमराह के लिए जगह है। आप चाहते हैं कि बॉलर अच्छे से चुने जाएं, उनके पास बॉलिंग के लिए बेहतरीन कंडीशन हैं, लेकिन उन्हें पता होगा कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। '

मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के मौजूदा साइकिल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह इस साइकिल में अब तक 43 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिराज को इस साल सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है और इस दौरान उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। साल 2020 में डेब्यू करने के बाद यह पहला मौका है, जब सिराज किसी विदेशी टेस्ट सीरीज में बिना कोई मैच खेले लौटेंगे।



इंडिया-न्यूजीलैंड टेस्ट

क्राइस्टचर्च टेस्ट में पहला दिन समाप्त....

न्यूजीलैंड का स्कोर 246/5 आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले दिन (27 नवंबर) स्टम्प तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 246 रन बना लिए. टॉम ब्लंडेल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर नॉटआउट हैं. भारत की ओर से आकाश दीप ने दो विकेट झटके हैं.

इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को फिर मौका नहीं मिला. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह गुरनूर बरार खेल रहे हैं. बरार का यह पहला टेस्ट मैच है.

पहली पारी में ऐसी रही है न्यूजीलैंड की बैटिंग

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने पहली पारी में दमदार शुरुआत की. कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की पार्टनरशिप की. अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे गुरनूर बरार ने खतरनाक दिख रहे कॉन्वे को 31 रनों के निजी पर आउट कर पवेलियन भेजा. ये विकेट पहले दिन लंच से पहले आखिरी गेंद पर गिरा. लंच के टॉम लैथम ने अपनी फिफ्टी पूरी की. लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे. लैथम का विकेट आकाश दीप ने लिया. फिर अंशुल कम्बोज ने हेनरी निकोल्स (16 रन) को आउट कर भारत को तीसरी कामयाबी दिलाई. 110 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड का एक और विकेट गिरा, जब आकाश दीप के बिछाए जाल में रचिन रवींद्र (0 रन) फंस गए.यहां से टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़कर मेजबान टीम को संभाला. मिचेल 31 रनों के निजी स्कोर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने, जिसके चलते ये साझेदारी टूटी. मिचेल के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने टॉम ब्लंडेल संग मोर्चा संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 62 रन जोड़कर न्यूजीलैंड को पहले दिन के खेल में कोई और नुकसान नहीं होने दिया.

33 मैच, 33 अलग मैदान... टेस्ट क्रिकेट में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

सचिन से भी आगे निकले यशस्वी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में एक दुर्लभ उपलब्धि अपने नाम की है. यशस्वी अपने शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले यह कारनामा भारत के संजय मांजरेकर ने किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में उतरते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया.

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका में टेस्ट डेब्यू किया था. तब से उनके सभी 33 मुकाबले अलग-अलग वेन्यू पर हुए हैं. मांजरेकर ने भी अपने शुरुआती 33 टेस्ट 33 मैदानों पर खेले थे.

यशस्वी ने सचिन को पछाड़

यशस्वी जायसवाल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं. मास्टर ब्लास्टर सचिन ने अपने शुरुआती 32 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन ने अपने पहले 24-24 टेस्ट अलग-अलग वेन्यू पर खेले थे.यशस्वी जायसवाल ने अब तक सात टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला है. इनमें इंग्लैंड के खिलाफ 10, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच-पांच, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार-चार, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ दो-दो तथा अफगानिस्तान के खिलाफ एक मुकाबला शामिल है.यशस्वी जायसवाल के पास 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में यह रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. नागपुर में 21 से 25 जनवरी तक होने वाले मुकाबले में खेलने पर उनका यह सिलसिला 34 मैचों तक पहुंच जाएगा.हालांकि, इसके बाद यह क्रम टूट सकता है. सीरीज के अगले चार टेस्ट चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. यशस्वी जायसवाल इन सभी मैदानों पर पहले ही टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं. ऐसे में नागपुर के बाद चेन्नई में उतरते ही उनका रिकॉर्ड बनाने का सफर थम जाएगा.

जयदेव उनादकट ने टी20 में रचा इतिहास

11वें नंबर पर खेली सबसे बड़ी पारी; 22 साल बाद टूटा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड



नई दिल्ली, एजेंसी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के 7वें चरण के मैच में एक विश्व कीर्तिमान बना। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तमिलनाडु और सौराष्ट्र के मुकाबले में। इस मैच में सौराष्ट्र के 11वें नंबर के खिलाड़ी और भारत के लिए खेल चुके जयदेव उनादकट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 11वें नंबर पर आते हुए 26 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में 11वें नंबर के बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी रही। आपको बता दें कि उन्होंने 22 साल पुराना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले टी20 में 11वें नंबर पर सबसे बड़ी नाबाद 24 रन की पारी ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एमएफ क्लीरी ने इंग्लैंड के एक घरेलू टी20 मैच में खेली थी। उन्होंने लीसेस्टर के लिए डरहम के खिलाफ नाबाद 24 रन 7 जुलाई 2004 को बनाए थे। अब 22 साल बाद 26 नवंबर 2026 को उनादकट ने यह रिकॉर्ड तोड़ा और नंबर 1 पर काबिज हो गए।

संक्षिप्त समाचार

मिस्र में तेल टैंकर में आग, 31 की मौत :21 से ज्यादा घायल; कई गाड़ियां भी जलीं



काहिरा, एजेंसी। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास हाईवे पर बुधवार रात एक तेल टैंकर में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 24 से ज्यादा कारें और बाइक जल गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। इसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग फैल गई। जलती गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अब आग पर काबू पा लिया गया है। हादसा काहिरा के उपनगर इम्बाबा के वाराक जिले में हुआ, जहां आग तेजी से कई कारों में फैल गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। घायलों को जायद स्पेशलाइज्ड, इम्बाबा जनरल और वर्राक सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान में 39 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। मिस्र में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होती है। तेज रफ्तार, खराब सड़कों और ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन न होना इन दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह हैं। इसी साल जनवरी में बेनी सुएफ प्रांत के पास कई गाड़ियों की भीषण टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 घायल हुए थे।

नाइजीरिया में 22.6 करोड़ डॉलर की मेथामफेटामाइन जब्त

नाइजीरिया , एजेंसी। नाइजीरिया की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी ने बुधवार को देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 22 करोड़ डॉलर मूल्य की मेथामफेटामाइन जब्त की। इस मामले में पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने एनुगु राज्य में बड़े पैमाने पर चल रही एक अवैध प्रयोगशाला पर छापा मारा। यहां से मेथामफेटामाइन बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के प्रवक्ता फेमी बाबाफेमी ने एक बयान में बताया कि इन लोगों को कथित तौर पर एक नाइजीरियाई नागरिक ने भर्ती किया था। वे फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में दाखिल हुए थे। बाबाफेमी ने कहा, 'अवैध रूप से संचालित इस फैक्टरी से कुल 1,512 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की गई। इसमें तैयार और निर्माणाधीन दोनों तरह की नशीली दवाएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 22.68 करोड़ डॉलर है। इस साल देश में की गई सबसे बड़ी जब्तियों में से यह एक है। नाइजीरिया अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसी साल मई में दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया में नाइजीरियाई और मैक्सिकन नागरिकों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। हाल के दिनों में इस तरह की कई कार्रवाइयां की गई हैं।

जापान : जंगली सब्जियों के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे लोग

टोक्यो, एजेंसी। ऑर्गेनिक खानपान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ते वैश्विक रुझान ने जापान की सदियों पुरानी जंगली सब्जियां चुनने की परंपरा को नया आकर्षण बना दिया है। यहां पर्यटक जंगलों और पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जियां जुटाने के लिए विशेष टूर और कार्यशालाओं पर सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर तक खर्च कर रहे हैं। 'सानसाई' नाम से पहचानी जाने वाली इन मौसमी पहाड़ी सब्जियों के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सानसाई की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वसंत ऋतु में पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले इन पौधों की 280 से अधिक किस्में बताई जाती हैं।

राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाया चार दिवसीय विशेष सत्र

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग दें

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने चार दिवसीय संसद सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को इसकी घोषणा कर बताया कि इस सत्र में महत्वपूर्ण सरकारी कार्य और विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इन महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा करें और संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग दें।

आगामी सत्र 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में शुरू होगा, जहां आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। इसके उपरांत, वहीं महत्वपूर्ण कार्य 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को विधिवत पत्र भेज दिया है।

कुछ सांसदों और मीडिया आउटलेट्स द्वारा की गई आलोचनाओं को संबोधित कर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इसतरह के हल्के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक या देशहित का कार्य होता है, केंद्र सरकार संसद का सत्र बुला सकती है, और यह एक स्थापित संसदीय परंपरा है। उन्होंने अतीत के उदाहरणों का हवाला दिया, जहाँ पिछले सत्र को स्थगित किए बिना भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं, यह दिखाता है कि यह संसदीय लोकतंत्र में कोई नई या असामान्य बात नहीं है। उनका मानना है कि जब केंद्र सरकार एक विशेष सत्र बुलाती है, तब इसका अर्थ ही कुछ विशेष, राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करना होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी दलों के नेताओं और सांसदों से पूरे दिल से अनुरोध किया कि वे लाए जाने वाले सभी विधेयकों पर अच्छी और गहन चर्चा करें। उन्होंने कहा कि सहमति या असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विशेष सत्र चलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने याद दिलाया कि देश के लोग संसद में होने वाली बहसों को सुनते हैं और भविष्य में उन्हें याद रखने वाले है। उन्होंने कहा कि संसद को सुचारु रूप से चलाना हम सभी सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को मजबूत करती है।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सत्र में पेश होने वाले विशिष्ट विधेयकों का विवरण अभी साझा नहीं किया, उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार बहुत महत्वपूर्ण कार्य लेकर आ रही है। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ इसमें अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि भारतीय लोकतंत्र की स्वस्थ और प्रभावी तस्वीर विश्व के सामने प्रस्तुत हो सके। रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार नियमों के तहत ही सत्र बुला रही है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है

ऋतब्रत बनर्जी की नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति रद्द

- कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर का आदेश किया खारिज, 10 दिन में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक नियुक्त किए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि 3 जून को जारी किया गया स्पीकर का आदेश कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर दोनों नियुक्तियों पर कानून के मुताबिक नए सिरे से विचार किया जाए। अदालत के फैसले के बाद अब ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां की नियुक्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुनाया। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी खेमे के गठन और उसके बाद की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। ऋतब्रत बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावती रुख अपनाते हुए 58 विधायकों के साथ अलग गुट बनाए जाने का दावा किया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 3 जून को उन्हें नेता प्रतिपक्ष और अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक नियुक्त किया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन नियुक्तियों की वैधानिक स्थिति पर विधानसभा अध्यक्ष को फिर से निर्णय लेना होगा।



ताजमहल से निकाली गई नक्काशीदार संगमरमर की पट्टिका ब्रिटेन में होगी नीलाम

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी द्वारा निकाली गई एक नक्काशीदार संगमरमर की पट्टिका अगले माह ब्रिटेन में नीलाम होने जा रही है। यह आयताकार पट्टिका उन दो पट्टिकाओं में से एक है, जिन्हें कर्नल पाउनोल फिप्स ने 1816 में आगरा और उसके आसपास की इमारतों की मरम्मत के अधीक्षक के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर एकत्र किया था। इस ऐतिहासिक कलाकृति की अनुमानित कीमत 20,000 से 30,000 पाउंड (करीब 24-36 लाख भारतीय रुपये) आंकी गई है। नीलामी लायन एंड टर्नबुल नीलामीकर्ता द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह विशेष नीलामी इस्लामिक और भारतीय कला से जुड़ी वस्तुओं को समर्पित होगी। नीलामीकर्ता की ओर से जारी विवरण के मुताबिक, इस संगमरमर की पट्टिका के साथ ताजमहल की एक पुरानी श्वेत-श्याम तस्वीर और दो महत्वपूर्ण पत्र भी संलग्न हैं। इन पत्रों में से एक कर्नल पाउनोल के पोते द्वारा छपवाया गया है, जबकि दूसरा मार्क्वेस ऑफ बाथ द्वारा हाथ से लिखा गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हैं। कर्नल के बेटे के संस्मरणों के मुताबिक, उनके पिता को ये वस्तुएं ताजमहल के भूमिगत हिस्से में मिली थीं, और उन्हें लगा था कि इनका इस्तेमाल मुगलकालीन स्मारक की मरम्मत के लिए किया जाना था। कर्नल फिप्स का जन्म 1780 में इंग्लैंड के डेवोन में हुआ था। 17वीं सदी की शुरुआत से ही सैनिकों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले फिप्स 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में कैडेट के तौर पर शामिल हुए थे। भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान, वह अन्य कार्यों के अलावा, ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, जो उनकी इस खोज की पृष्ठभूमि बनती है। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 1816 में कर्नल को लोअर प्रोविंसेस में इमारतों का अधीक्षक नियुक्त किया और उन्हें आगरा छोड़कर तत्कालीन कलकत्ता जाना पड़ा। वह और उनका परिवार 1823 में ब्रिटेन लौटा और फिप्स की मृत्यु 1858 में हुई। यह पट्टिका 200 से अधिक वर्षों तक उनके परिवार के संग्रह का हिस्सा बनी रही, जो अब नीलामी के लिए प्रस्तुत की गई है और एक बार फिर इसके मूल स्थान से लिए जाने के इतिहास को उजागर करेगी।

खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, गठबंधन से इतर विपक्षी दलों को भी भेजा न्यौता

-परिसीमन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कांग्रेस का आखिरी दांव

नई दिल्ली , एजेंसी । परिसीमन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सरकार के संभावित कदम के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली स्थित खड़गे के आवास 10, राजाजी मार्ग पर होगी।

प्रस्तावित बैठक में सरकार की ओर से परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में पेश किए जाने की स्थिति में संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का प्रयास है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर सरकार के कदम का संसद के भीतर मजबूती से विरोध किया जाए।



बैठक के लिए 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों के अलावा गठबंधन से बाहर के विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें द्रमुक (डीएमके), आम आदमी पार्टी (आप) और बीजू जनता दल (बीजेडी) प्रमुख हैं। इसके अलावा एनसीपी (शरद पवार) समेत अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन दलों को साथ लाने की है, जो 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। पार्टी का मानना है कि यदि डीएमके, बीजेडी, आप और एनसीपी (शरद पवार) समेत अन्य दल एक साझा रणनीति पर सहमत होते हैं तो सरकार के लिए विधेयक को आगे बढ़ाना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं, सरकार भी इस मुद्दे पर अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। बैठक में विपक्षी दलों के बीच इसी रणनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।

बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री आवास और विधान सौध को उड़ाने की फर्जी धमकी, एक गिरफ्तार

बेंगलुरु,एजेंसी। ।बेंगलुरु में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के आवास और प्रतिष्ठित विधान सौध को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी देने के आरोप में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कार्तिक आर. के रूप में हुई है, जो ब्यादरहल्ली इलाके के बालाजीनगर का निवासी है। यह धमकी पांच नवंबर को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि कार्तिक ने ऑटो-रिक्शा बुकिंग ऐप के माध्यम से यह धमकी दी थी। पांच नवंबर की शाम को एक ऑटो-रिक्शा चालक को एप पर पैलेस नगर से राजराजेश्वरी नगर तक की बुकिंग मिली थी। जब चालक ने ग्राहक को लेने के लिए फोन किया, तब कथित तौर पर कार्तिक ने खुद को मुख्यमंत्री के आवास के अंदर बताया। उसने चालक को गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी को फोन देने को कहा और धमकी दी कि उसने उपमुख्यमंत्री के आवास और विधान सौध में बम लगाए हैं, जो मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने पर फट जाएंगे। पुलिसकर्मी ने तत्काल ऑटो की जांच की और मामले की गंभीरता को समझा। शुरुआत में बीमार रिश्तेदार की देखभाल में व्यस्त होने के कारण चालक तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा सका। हालांकि, बाद में चालक ने सात नवंबर को सदाशिवनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी कार्तिक आर. को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(4) (आपराधिक धमकी) और 353(1)(बी) (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अमेरिका में थैंक्सगिविंग पर तूफान का साया: न्यूयॉर्क में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट, न्यू जर्सी में आपातकाल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका में थैंक्सगिविंग से पहले भीषण तूफानों ने छुट्टियों के जश्न और यात्रा की तैयारियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते न्यूयॉर्क की मशहूर मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं, फिलाडेल्फिया में आयोजकों ने मौसम संबंधी चिंताओं के कारण परेड में गुब्बारे नहीं उड़ाने का फैसला किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की मैसीज परेड शनिवार सुबह 8:30 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) शुरू होगी। यह फैसला भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है। दोनों तटों पर तूफान का असर थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के दौरान



अमेरिका में आठ करोड़ से ज्यादा लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी तट पर खराब मौसम से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वी तट पर सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद सबसे ऊंचे जलस्तर की आशंका जताई गई है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। पश्चिमी तट पर भी तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में पैसिफिका इलाके में तेज लहरों के कारण एक पियर का हिस्सा ढह गया। वहीं, सैन डिएगो के आसपास ऊंचे ज्वार के कारण जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड टूट गए।

खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइंस ने भी यात्रियों को संभावित परेशानी के लिए आगाह किया है। साउथवेस्ट एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने थैंक्सगिविंग के दिन पूर्वोत्तर अमेरिका में उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी बड़े तूफान की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में आपातकाल घोषित किया है। तूफान के कारण तेज और नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं, भारी बारिश, तटीय इलाकों में बाढ़ और लंबे समय तक बिजली गुल रहने की आशंका है। यह आपातकालीन घोषणा बुधवार शाम छह बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) से प्रभावी हुई। गवर्नर शेरिल ने छुट्टियों में यात्रा करने वाले लोगों से अपील की कि वे तूफान के सबसे खराब असर से बचने के लिए बुधवार को ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करें।

बांग्लादेश- अवामी लीग ने 2 दिन बंद का ऐलान किया



ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशभर में दो दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपने लॉकडाउन के पीछे 8 मांगें रखी हैं। इनमें पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाना और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना शामिल है। वहीं, सरकार ने हसीना की वापसी और बढ़ती हिंसा को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस बीच, सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में देशभर में आगजनी की करीब 100 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सीमा पर बॉर्डर सेना की 108 टुकड़ियां तैनात : हसीना की वापसी से पहले तारिक रहमान सरकार ने सीमा से लगे सात जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 108 टुकड़ियां तैनात की हैं। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन, बॉडी कैमरों और दूसरे निगरानी उपकरणों की मदद से नजर रख रही हैं। पुलिस ने भी सीमा से लगे इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। जगह-जगह जांच चौकियां बनाई गई हैं और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, सीमा से लगे 30 जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन में ग्रामीण बैंक की 100 शाखाओं पर हमला : बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मुहम्मद यूनुस की ओर से बनाए गए ग्रामीण बैंक की शाखाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैंक की 24 नवंबर की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर से अब तक देशभर में इसकी करीब 100 शाखाओं पर हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अवामी लीग को कभी राजनीति नहीं करने दी जाएगी। पार्टी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहने-सुनने के समझौते के तहत नई दिल्ली से बातचीत जारी है। हसीना की सत्ता जाने के बाद से सरकार पर विरोध की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच पत्रकारों को गिरफ्तारी, हिंसा, मुकदमों और आर्थिक रोक का सामना करना पड़ा।

किम जोंग उन ने किया परमाणु ठिकानों का दौरा, सामरिक हथियारों के व्यापक इस्तेमाल पर रहा जोर

सोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बुधवार को देश के परमाणु ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु हथियार उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया। परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्रों और हथियार अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण करते हुए उन ने कहा कि देश को अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, किम ने बुधवार को इन परमाणु ठिकानों का दौरा किया। हालांकि, उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों के नाम और उनके स्थान का खुलासा नहीं किया। निरीक्षण के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता का व्यवस्थित और लगातार विस्तार कर रहा है, ताकि देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूत और आधुनिक बनाया जा सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की क्षमता विकसित करने को महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता बताया।

किम ने इसके पीछे आधुनिक युद्ध में सामरिक परमाणु हथियारों



की सैन्य उपयोगिता और उत्तर कोरिया की उस देश के साथ साझा सीमा का हवाला दिया, जिसे उन्होंने सबसे खतरनाक शत्रु देश बताया। उनका इशारा दक्षिण कोरिया की ओर था। उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिका पर पूर्वोत्तर एशिया में परमाणु प्रसार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा,' अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियार साझा करने और उनके संयुक्त इस्तेमाल की व्यवस्था विकसित कर रहा है। इससे क्षेत्र में एक वैश्विक परमाणु सैन्य गठबंधन प्रणाली तैयार हो रही है। किम ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में उत्तर कोरिया के लिए अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति संपन्न देश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और बाहरी देशों के बयानों या परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्तर कोरिया ने वर्ष 2023 में अपने संविधान में खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित किया था। किम ने कहा कि परमाणु हथियारों का स्वामित्व देश की संप्रभुता और सुरक्षा की बुनियादी गारंटी है। इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश को उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता पर हमला और युद्ध की घोषणा के रूप में देखेगा। इस साल फरवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की नौवीं कांग्रेस में भी उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु हथियार संपन्न देश की स्थिति को अपरिवर्तनीय बताया था।

उस दौरान प्योंगयांग ने पांच वर्षीय सैन्य आधुनिकीकरण योजना के तहत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। यह किम जोंग उन का किसी परमाणु केंद्र का चौथा ऐसा दौरा है, जिसकी जानकारी सरकारी मीडिया ने सार्वजनिक की है। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2024, जनवरी 2025 और जून 2026 में भी परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कांलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com